सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 22 दिसंबर, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 86, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

दिल्ली का प्रदूषण हटाने के लिए कितना कारगर होगा चीनी फार्मूला?

पंकज श्रीवास्तव

दिल्ली की ज़हरीली हवा भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदा बन चुकी है। पर सवाल है कि जब चीन ने बीजिंग की हवा सुधार ली, तो भारत क्यों नाकाम है? क्या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा दमघोंटू हवा में दम तोड़ रहा है?

कभी मुहावरेदार भाषा में कहा जाता था कि हवा में ज़हर फैल गया है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के लिए यह मुहावरा नहीं ख़ौफ़नाक हक़ीक़त है। दिसंबर में ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ। एक दशक पहले चीन की राजधानी बीज़िंग का भी यही हाल था, लेकिन आज वहाँ स्थिति पूरी तरह क़ाबू में है। आख़िर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? न दिल्ली का पानी साफ़ है, न यहाँ की हवा ही साँस लेने लायक़ है। यह कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, दिल्ली की हवा के ज़हरीले होने का बयान था और इसे कोई झुठला नहीं सका।

दिसंबर में दिल्ली का AQI आमतौर पर 300-500 के बीच रहा जो गंभीर श्रेणी है। नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, गुरुग्राम यानी पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है जहाँ हवा में PM2.5 का स्तर WHO की सीमा से 20-30 गुना ज्यादा है। PM2.5 का मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। पार्टिकुलेट मैटर हवा में मौजूद बहुत छोटे ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण हैं। इनमें इनकार्बनिक आयन्स, आर्गेनिक कार्बन से लेकर मेटल और मिनिरल डस्ट तक मिली होती हैं। हवा में मौजूद इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है।

ये महीन कण खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये सांस के जरिए फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं और खून में घुल सकते हैं। इससे अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और यहां तक कि कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि PM2.5 का स्तर पचास से कम हो।

एक्यूआई (AQI - Air Quality Index) यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। यह एक नंबर है जो बताता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। यह मुख्य रूप से PM2.5, PM10 जैसी श्रेणियों में मापा जाता है। ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को मापकर AQI कैलकुलेट किया जाता है। वैश्विक स्तर पर ज्यादातर देश US EPA का AQI स्केल इस्तेमाल करते हैं, जो 0 से 500 तक होता है। S EPA का पूरा नाम United States Environmental Protection Agency है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा की गई थी। भारत में भी यही स्केल है। वैश्विक पैमाने पर AQI को 6 कैटेगरी में बांटा जाता है, हर एक का अपना रंग कोड होता है:

कुछ स्थायी कारण भी हैं जो दिल्ली की हवा ख़राब करते हैं-जैसे पराली जलानाः पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसान फसल अवशेष जलाते हैं। सर्दियों में हवा ठंडी और स्थिर होने से धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है। CPCB के अनुसार, ये 30-40% तक योगदान देता है।

वाहनों का धुआंः सड़क परिवहन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। पुरानी गाड़ियां, डीजल व्हीकल और ट्रैफिक जाम से NO& और PM2.5 बढ़ता है। ये 20-30% प्रदूषण का कारण है।

कंस्ट्रक्शन और रोड डस्टः लगातार निर्माण कार्य से धूल उड़ती है, जो 30-40% PM का स्रोत है। उद्योग और कोयलाः आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया और कोल बेस्ड पावर प्लांट से प्रदूषण।

सर्दियों का मौसमः ठंड में हवा नीचे रहती है, प्रदूषक फंस जाते हैं - इसे इनवर्शन कहते हैं।

ये सब मिलकर स्मॉग बनाते हैं, जो आंखों में जलन, खांसी और सांस की बीमारियां पैदा करता है।

भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक कहते हैं कि सर्दियों में दिल्ली की हवा से सांस लेना मुश्किल है- आंखें जलती हैं, सिर दर्द होता है।

हाल ही में सिंगापुर हाई कमीशन ने एडवायजरी जारी करके अपने नागरिकों को कहा कि घर में रहें, मास्क पहनें, बच्चे और बुजुर्ग बाहर न निकलें।

दिल्ली में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने X पर बीजिंग की कहानी की याद दिलाते हुए बताया है कि कैसे चीन ने राजधानी बीजिंग को प्रदूषण मुक्त बनाया है।

यू जिंग ने दिल्ली और बीजिंग का हाल बताता एक्यूआई मैप पोस्ट किया। इसमें बीजिंग में एक्यूआई 67 और दिल्ली का 447 था। वाक़ई यह चीन की बड़ी सफलता है। 10-15 साल पहले बीजिंग की हालत दिल्ली से भी बदतर थी। 2010-2013 में बीजिंग को 'स्मॉग कैपिटल' कहा जाता था। AQI 500-1000 तक पहुंच जाता था। लेकिन चीन ने 'वार ऑन पॉल्यूशन' पॉलिसी घोषित की और कमाल कर दिखाया।

चीन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये कदम उठाये- कोल बर्निंग बंद की, कोल प्लांट्स बंद या गैस पर शिफ्ट। 3000 से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज बंद या शिफ्ट कीं।

व्हीकल्स पर सख्त नियमः पुरानी गाड़ियां फेज आउट, लाइसेंस प्लेट लॉटरी से नई गाड़ियां कंट्रोल, ऑड-ईवन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट - मेट्रो और बसें बढ़ाईं।

रीजनल कोऑर्डिनेशनः आसपास के प्रांतों के साथ मिलकर काम। अब बीजिंग का AQI ज्यादातर 50-100 के बीच रहता है। ह रिपोर्ट्स में इस सफलता को मिसाल माना गया है।

कुछ लोगों का कहना है कि चीनी मॉडल को अपनाना चाहिए, वहीं कुछ लोग चीन की इस उपलब्धि को भी षड्यंत्रों से जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर ठान लिया जाए तो जो बीजिंग में हो सका, वह दिल्ली में भी हो सकता है। पर पहले इसे मुद्दा तो माना जाये। पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था लेकिन इस बार दिवाली के ऐन पहले ग्रीन पटाखों के नाम पर सीमित छूट दी गयी तो जनता ने इसे असीमित बना दिया। जमकर पटाखे चले और उसके बाद खाँसी का जो दौर चला है, वह अब तक नहीं थमा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि प्रदूषण से निजात पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।

दिल्ली में डाक्टर बच्चों और बुज़ुर्गों को लेकर ख़ासतौर पर चिंतित हैं। उनका कहना है कि साँस की दिक़्क़त हो तो दिल्ली छोड़ देना ही ठीक होगा, यानी कोई इलाज कारगर नहीं है। कोई नहीं जानता कि दिल्ली की बर्बादी की ये कहानी कब और कैसे बदलेगी। हालात को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि पहले स्वीकार किया जाये कि हालात ख़राब हैं। लेकिन जिन्हें लगता है कि भारत विश्वगुरु बन गया है वह विष फैलने की बात मान भी कैसे सकते हैं। यह झूठा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी समस्या है।

(सत्य हिंदी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस ने ही बसाए, उन्हें बचा भी रही

असम में मोदी बोले-इसलिए एसआईआर का विरोध कर रही

डिब्रूगढ़ (एजेंसी)। असम दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में अमोनिया-यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन होगी। यह यूनिट 2030 तक चालू हो जाएगी। इस दौरान जनसभा को

- **प्रधानमंत्री मोदी ने डिब्रूगढ़ में किया यूरिया प्लांट का उद्घाटन**

संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थीं। जो काम कांग्रेस को उस समय करना था, उसने नहीं किया। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया है और कांग्रेस ही उन्हें

बचा रही है। एसआईआर का विरोध कर रही है। तुष्टिकरण और वोट बैंक के इस कहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि असम की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा फौलाद बनकर खड़ी है। इससे पहले पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर 25 बच्चों के साथ करीब 45 मिनट परीक्षा पे चर्चा भी की। मोदी ने नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्प लिमिटेड के मौजूदा परिसर में नए फर्टिलाइजर यूनिट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के बाद शहीद स्मारक पहुंचे। जहां 1985 में अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

पीएम के कार्यक्रम में 12 जिलों के बच्चे शामिल हुए

मोदी के दौरे के मद्देनजर शनिवार से 2 दिनों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर फेरी सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। परीक्षा पे चर्चा से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। नदी पुलिस, एनडीआरएफ और सेना के जवान सुबह से ही गश्त करते दिखे। इवेंट में भाग लेने वाले छात्रों को कामरूप मेट्रोपॉलिटन, मोरीगांव, डिब्रूगढ़, कछार, श्रीभूमि, बक्सा, दीमा हसाओ, कोकराझार, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नलबाड़ी जिलों के स्कूलों से चुना गया था।

हमारा लक्ष्य असम को शक्तिशाली बनाना है

हमारा लक्ष्य असम को उतना ही शक्तिशाली बनाना है जितना वह सदियों पहले अहोम राजवंश के समय था। हमारे किसानों को खाद की सप्लाई मिलती रहे। डिब्रूगढ़ का यह फर्टिलाइजर प्लांट किसानों की जरूरत को पूरा करेगा। इसमें 11 हजार करोड़ रुपए इंवेस्ट किए जाएंगे। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी और पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म होती गई। तो ऐसे समय में तब की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक समय किसानों के क्या हालात थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में घंटों-घंटों तक लगना पड़ता था। यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी। पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी-चोटी की ताकत लगा रही है।

खेल हमारी संस्कृति का प्रमुख पक्ष, हमने बनाया है खेलों को शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा : सीएम डॉ. यादव

- **मुख्यमंत्री ने इन्दौर में 7वें नेशनल रैंकिंग पिकलबॉल टूर्नामेंट को किया संबोधित**

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खेल हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम अंग रहा है। हमारे व्यक्तित्व के विकास में एक प्रमुख पक्ष के रूप में खेलों में हमारे जीवन को दिशा दी है। हमने खेलों को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। हमारे खिलाड़ी प्रायः हर खेल में देश और हैं। इससे न केवल नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, बल्कि खेल अधोसंरचना के विकास को भी नए आयाम मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक प्रगति करने वाला राज्य बन रहा है। औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों, कुटीर एवं ग्रामोद्योग सहित कृषि एवं

प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खिलाड़ियों से आव्हान किया कि वे चाहे जिस किसी भी खेल के खिलाड़ी रहें, अपनी लगन और मेहनत से हमेशा अपना उत्कृष्ट देने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इन्दौर में एक निजी स्कूल द्वारा आयोजित 7वें नेशनल रैंकिंग पिकलबॉल टूर्नामेंट-2025 को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश राज्य ऑलम्पिक एसोशिएशन के संरक्षक भी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैदिककाल से हमारी संस्कृति में खेलों का बड़ा योगदान रहा है। कई मामलों में भारतीयों ने अपने दौर से भी आगे बढ़कर विश्व में खेलों में नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नवनिर्माण में खिलाड़ियों की भी अहम भूमिका है। खिलाड़ियों के योगदान से हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहे संबंद्ध क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मध्यप्रदेश का सर्वाधिक योगदान होगा। निजी स्कूल के अध्यक्ष श्री स्वप्निल कोठारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुरुषार्थ से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे मोबाइल की रील से बाहर निकलें, मैदान में आकर परिश्रम करें, तभी वे देश के लिए पसीना और रक्त बहाने के योग्य बनेंगे। उन्होंने सभी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संकल्प 'अभ्युदय मध्यप्रदेश' में सक्रिय रूप से सहभागी बनकर अधिकतम योगदान देने की अपील की।

कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्री बलवंत, श्री गणेश अग्रवाल, श्री गोपाल अग्रवाल, श्री सुनील सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक इसलिए हालात हो रहे मुश्किल

- **मोहन भागवत बोले-हमें सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए, क्योंकि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश**

कोलकाता (एजेंसी)। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हालात मुश्किल हैं। हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो एकजुट रहना होगा। दुनियाभर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर कोलकाता में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में रविवार को बोल रहे थे। भागवत ने कहा- भारत को अपनी सीमाओं में रहकर जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। हमें वह सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत ही है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। उन्हें कुछ करना होगा। हो

सकता है वे (सरकार) पहले से ही कुछ कर रहे हों। कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताई जा सकतीं। कभी नतीजे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। इसे साबित करने की जरूरत नहीं, जैसे सूरज पूरब से उगता है। हमें नहीं पता कि यह कब से हो रहा है। तो, क्या इसके लिए भी हमें संवैधानिक मंजूरी चाहिए। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है और भारतीय संस्कृति की सराहना करता है वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र मानता है। यह संघ की भी विचारधारा है। अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके शब्द (हिंदू राष्ट्र) जोड़ने का फैसला करती है। फिर चाहे वे ऐसा करें या न करें, कोई बात नहीं।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...रेलवे ने बढ़ा दिया है किराया

हर किमी पर 1-2 पैसे ज्यादा लगेंगे, 26 दिसंबर से होगा लागू

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि, 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे रूट और सीजन टिकट वालों को राहत रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा, रोजाना

सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने सब-अर्बन (उपनगरीय) ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे को क्यों पड़ी किराया बढ़ाने की जरूरत। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, यह किराया बढ़ोतरी ऑपरेशनल कॉस्ट (परिचालन लागत) में हो रही वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जरूरी है। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनें चलाने और स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है।

भोपाल से दिल्ली जाने के लिए अब 16 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे

इस किराया बढ़ोतरी से मिली 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं कामों में किया जाएगा। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।

शरद की सुबह

प्रिया की
हथेलियों के ताप का
प्रथम स्पर्श,और
वासन्तिक ताप से स्पंदित
हवा के संस्पर्श में
जितना साम्य और
सगापन होता है
उसे मेहसूस कर मैं
नि :शब्द हो जाता हूँ

ग्रीष्म की तपन और
पसीजते पसीने से
बेहाल होने पर
तुम्हारे लहराते
आँचल की गुलमोहरी छाँह
हरियाते दरख्त सी लगती है

तुम्हारे शीतल दो नैनों की
रक्तिम डोर में टँके पुष्प
जब गुपचुप
बतियाने लगते हैं,तब भी
मैं,नि :शब्द हो जाता हूँ

सावन की पहली फुहार
की सहलाहट
और कुनमुनाती माटी-देह से
उठती भाप की
सौंधी सुवास में, और
प्रथम आलिंगन के ताप-सिंचित साँसों की
आवाजाही के एहसास को जज्ब करने के बाद भी
नि :शब्द हो जाता हूँ

नि :शब्द हो जाने के
इन लम्हों को बचा के रख
जब तब
स्फुरित होते प्रेम का
आस्वाद लेते रहता हूँ...ताउम्र
नि :शब्द होकर।

– अरुण सातले

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c | न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 22 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

दिल्ली में बहुत जल्द ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार

- अप्रैल-2026 से लागू होगी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में मॉर्डनाइजेशन लाने के लिए रेखा सरकार ने नई इलेक्ट्रिक विहिकल (ईवी) पॉलिसी का खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए

हैं कि यह पॉलिसी अगले वित्त वर्ष, यानी अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पॉलिसी से पहले चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर रहेगा।

यूपी में किसानों को सीएम योगी की सौगात

- अब 6 फीसदी पर मिलेगा लोन,2 करोड़ को फायदा

लखनऊ (एजेंसी)। सीएम योगी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने रविवार को किसानों के लिए 6 फीसदी ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। फिलहाल

किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से 11.50 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिलता है। योगी के ऐलान के बाद किसानों को सस्ते दर पर लोन मिलेगा, बचा हुआ हिस्सा सरकार चुकाएगी। योगी ने कहा- यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.50 फीसदी है। इससे किसानों पर बोझ बढ़ता है। सरकार इसे कम करने की दिशा में बढ़ रही है। लघु और सीमांत किसान को यह लोन अब महज 6 पर मिलेगा।

तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी

- उदयनिधि स्टालिन बोले, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को नागोर के एक कार्यक्रम में केन्द्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- तीन-भाषा नीति की

आड़ में राज्य पर हिंदी थोपने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। उदयनिधि स्टालिन ने डॉ जे जयललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी में ईसाई मुरुसु नागोर इस्माइल मोहम्मद हनीफा के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि तमिलनाडु में पॉलिसी लागू नहीं की इसलिए शिक्षा निधि के 2,000 करोड़ रुपए रोके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएं।

नए साल में बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रूप में चुन लिया। इनके हाथों में ही आने वाले समय में भाजपा की

- कैबिनेट विस्तार की भी सुगबुगाहट, नए लोगों को मिलेगा मौका

कमान जाने वाली है। इसके बाद अब संगठन में फेरबदल के कयास तेज हो गए हैं। खबर है कि भाजपा में संगठन चुनावों की प्रक्रिया अगले माह पूरी होने के साथ ही बड़े बदलावों की शुरुआत हो जाएगी। ये बदलाव केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार में भी दिखाई देंगे। जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार भी देखने को मिल सकता है। संगठन विस्तार की प्रक्रिया सभी स्तरों पर लागू होने में लगभग छह माह का समय लग सकता है। संगठन में युवा और अनुभव का अनुपात लगभग आधा-आधा रहेगा और सरकार में भी करीब छह माह के भीतर इसी तरह का संतुलन देखने को मिलेगा। युवा नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब भविष्य की पार्टी तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे नेतृत्व को आगे लाया जाएगा, जो अगले दो दशकों तक पार्टी को विभिन्न स्तरों पर आगे ले जा सके।

केंद्र सरकार में नए चेहरों को प्रमुखता मिलेगी

सूत्रों के अनुसार, संसद के बजट सत्र के बाद केंद्र सरकार में भी फेरबदल की संभावना है और इसमें नए चेहरों को प्रमुखता दी जाएगी। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में अभी तक मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संगठन की नई टीम के गठन के बाद इसकी संभावनाएं जरूर बनेंगी। इसमें सरकार की आवश्यकताओं, राजनीतिक परिस्थितियों और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखा जाएगा।

हरदा में करणी सेना अध्यक्ष बोले-

आश्वासन नहीं, लिखकर दे प्रशासन...प्रदर्शन जारी

लाठीचार्ज के आरोपी पुलिसवालों को हटाने, मजिस्ट्रियल जांच का भरोसा

हरदा (नप्र)। हरदा के नेहरू स्टेडियम में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना परिवार का जनक्रांति आंदोलन लगातार जारी है। इसमें 20 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। इसे जिले के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है।

वहीं शाम को करणी सेना का सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रशासन ने हरदा में हुए लाठीचार्ज के आरोपी पुलिस कर्मियों को हटाने और उनके खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच कराने का भरोसा दिया है, लेकिन यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया है। मकराना ने प्रशासन से लिखित में आदेश देने की मांग की है।

अनशन पर बैठे शेरपुर, हर दो घंटे में चेकअप- करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने मंच पर अनशन शुरू

कर दिया है। डॉक्टरों की टीम हर दो घंटे में उनका हेल्थ चेकअप कर रही है। फिलहाल, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है। हालांकि शुगर में घटाव-बढ़ाव जारी है।

मांगें नहीं मानने पर भोपाल-दिल्ली कूच की चेतावनी- इससे पहले करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मांगें नहीं मानने पर भोपाल और दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले में पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रदर्शन स्थल से लेकर जिले के सभी प्रवेश और निकास मार्गों तक कड़ी निगरानी की जा रही है। बाहर से बुलाए गए पुलिस बल के ठहरने के लिए शहर के करीब 30 होटल और धर्मशालाएं प्रशासन के नियंत्रण में ली गई हैं। करणी सेना परिवार की मांगों में न्यायिक जांच, केस वापसी, आरक्षण व भर्ती प्रक्रिया में सुधार, आर्थिक आधार पर आरक्षण, किसानों से जुड़े मुद्दे, बिजली बिल व स्मार्ट मीटर, शिक्षा-रोजगार, महिला सुरक्षा, गो-संरक्षण, पूर्व सैनिकों और मीडिया कर्मियों से संबंधित मांगें शामिल हैं।

छह अरब मोबाइल यूजर को अब मिलेगी बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी

इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक, 24 दिसंबर को होगा लॉन्च, बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के आगामी 'एलवीएम 3 एम 6 मिशन' के तहत 24 दिसंबर को 'ब्लू बर्ड ब्लॉक-2' उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन अमेरिका में स्थित एएसटी स्पेसमोबाइल के

साथ हुए वाणिज्यिक समझौते का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक मिशन के तहत अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह को तैनात किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई-स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। एएसटी स्पेसमोबाइल (एएसटी एंड साइंस, एलएलसी) पहला और एकमात्र अंतरिक्ष-आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क विकसित कर रहा है, जो सीधे स्मार्टफोन के माध्यम से सुलभ है और वाणिज्यिक व सरकारी दोनों अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है।

परेड के साथ सैन्य शक्ति में भी होगा खास नजारा

पहली बार जनता के बीच होगा सेना दिवस समारोह

जयपुर (एजेंसी)। सेना दिवस के मौके पर अब सैन्य छावनियों में बड़े बड़े आयोजन होते थे लेकिन इस बार यह कार्यक्रम जनता के बीच होंगे। राजस्थान में पहली बार जयपुर की धरती पर सैन्य समारोह होंगे। जयपुर

- सीकर रोड पर 'नो योर आर्मी' हथियार प्रदर्शनी भी लगेगी

के जगतपुरा स्थित महल रोड सेना के जवानों की ओर से परेड का आयोजन किया जाएगा। इस तरह की परेड अमूमन दिल्ली में होती रही है लेकिन पहली बार परेड के लिए जयपुर को चुना गया। 15 जनवरी को सेना दिवस पर जयपुर की धरती पर सैन्य परेड होने के साथ कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। 15 जनवरी 2026 को परेड के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है। सेना की परेड में भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट की टुकड़ियां इसमें हिस्सा लेंगी। करीब तीन किलोमीटर तक इस परेड का आयोजन होने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर भी इस मार्च पास्ट में शामिल किए जाएंगे। इससे परेड की भव्यता और बढ जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे टैंक भी शामिल किए जाएंगे। 15 जनवरी को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस में सेना के जवानों की ओर से कई तरह के सैन्य इवेंट आयोजित किए जाएंगे। लाइट और साउंड शो के जरिए यह बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना ने किस तरह युद्ध लड़ा और दुश्मन को परास्त किया। सेना के जवान मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी करेंगे। ड्रोन के जरिए भी सेना के इवेंट की कई कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जयपुर के सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड में सेना की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हमारी सेना में पहले कैसे हथियार थे और अब कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार शामिल किए गए हैं।

ऊधमपुर में एक घर से खाना लेकर फरार हुए तीन आतंकी

- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने शुरू कर दिया सर्च अभियान

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक घर से आतंकवादियों के कथित रूप से भोजन लेकर पास के जंगल में भागने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाश अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बल, मजालता क्षेत्र के चोरे मोटू गांव और उससे सटे वन क्षेत्रों में संयुक्त तलाश अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह इलाका उस स्थान से करीब पांच किलोमीटर पश्चिम में है, जहां पहले हुई एक मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी।

बिहार में उपेन्द्र कुशवाहा की राह में अटक गए रोड़े

नितिन नबीन और पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा !

- एनडीए के गुणा-भाग में फिट नहीं हो पा रहे उपेन्द्र

पटना (एजेंसी)। बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव में अभी तीन महीने का समय शेष है, लेकिन 5 सीटों के लिए होने वाले इस संग्राम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उच्च सदन भेजेगी। वहीं, चर्चा यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार खाली हाथ रहना पड़ सकता है। 9 अप्रैल 2026 को

बिहार से राज्यसभा के जिन 5 दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें राजद के प्रेम चंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह (एडी सिंह), जदयू के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। इनकी सीटों पर चुनाव होगा। इस बार राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।

जदयू कोटे में हरिवंश और रामनाथ ठाकुर पर संशय

जदयू कोटे से जिन दो नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। दोनों ही नीतिश कुमार के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नीतिश कुमार आमतौर पर किसी नेता को दो से ज्यादा बार राज्यसभा भेजने से बचते रहे हैं, लेकिन पद और राजनीतिक हैसियत को देखते हुए दोनों के रिपीट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा।

भाजपा कोटे से नितिन नबीन का राज्यसभा जाना लगभग तय

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके नितिन नबीन को लेकर पार्टी के भीतर तस्वीर काफी हद तक साफ मानी जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के दो दिन बाद उन्होंने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, वे जल्द विधायकी से भी इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति में कदम रख सकते हैं। बीजेपी में यह परंपरा रही है कि राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष पद पर वही नेता होते हैं, जो संसद का हिस्सा हों। ऐसे में नितिन नबीन को पहले राज्यसभा भेजकर केंद्र की राजनीति में स्थापित करने की तैयारी मानी जा रही है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले

- 213 सीटें जीती, भाजपा सबसे ज्यादा 118 पर विजयी
- शिंदे को 58 सीटें मिलीं, उद्धव की पार्टी 9 पर ही सिमटी

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बंपर जीत हासिल हुई है। रविवार को जारी हुए 288 सीटों (246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों) के रिजल्ट में महायुति को 213 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन में भाजपा 118 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58 सीटें, एनसीपी अजित को 37 सीटें मिलीं। वहीं, विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के हिस्से केवल 51 सीटें ही आईं। इसमें कांग्रेस 31, शिवसेना उद्धव को 9, शरद पवार की एनसीपी को केवल 10 सीटें ही मिलीं। 24 सीटें अन्य को मिली हैं, जिन्होंने स्थानिक अघाड़ी (लोकल अलायंस) बनाया था। दरअसल, महाराष्ट्र 288 नगर परिषदों और नगर पंचायत के लिए दो चरणों में चुनाव हुआ था। पहले चरण में 2 दिसंबर को 263 निकायों में मतदान हुआ था। बाकी 23 नगर परिषदों और कुछ खाली पदों पर 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी।

अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा

बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों को लेकर एजेंसियां अलर्ट

ईटानगर (एजेंसी)। अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क के खुलासे और सीमा से जुड़ी गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस बीच, स्थानीय लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना की मौजूदगी और संभावित घुसपैठ की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सेना की गतिविधियों और अन्य संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर्स तक भेज रहे थे। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के चीन से जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे 'हाइब्रिड वॉर' की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें जासूसी, घुसपैठ और सैन्य दबाव को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों का दावा है कि सितंबर 2024 से चीनी सेना ने अंजाव जिले के कपापु क्षेत्र में करीब 60 किमी अंदर तक कैंप बनाए हैं। उनका कहना है कि हालात 2022 जैसे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से इसे 'ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग' बताया जा रहा है। इसी दौरान तिब्बत के ल्हुंजे एयरबेस पर चीन की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। यहां मैकमोहन लाइन

से करीब 40 किमी दूर 36 हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए जाने और स्टेल्थ जेट्स की तैनाती की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध स्थानीय मुस्लिम समुदायों में घुल-मिलकर स्लीपर सेल विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बांग्लादेशी युवकों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। वेस्ट सियांग के एसपी का कहना है कि यह मामला असम और अरुणाचल से जुड़े एक बड़े जासूसी मॉड्यूल

- पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला, चीन की हलचल पर भी नजर

का हिस्सा हो सकता है। एजेंसियां इसे ऐसी रणनीति से जोड़कर देख रही हैं, जिसमें पाकिस्तान प्रॉक्सी की भूमिका निभा सकता है। 11 दिसंबर को ईटानगर से जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नजीर अहमद मलिक और सबीर अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। दोनों कंबल विक्रेता बनकर घूम रहे थे और एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। जांच के मुताबिक,उन्हें अवैध घुसपैठ में मदद व कूरियर बनने के निर्देश मिले थे।

परिक्रमा

विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए विशेष सत्र

अरुण पटेल

लेखक
सुबह सवेरे के
प्रबंध संपादक हैं

विधानसभा की 70वीं वर्षगांठ पर विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश के विजन पर एक दिवसीय विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने संकल्प व्यक्त किया है कि जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर हम प्रदेश का एक नया इतिहास लिखेंगे। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने और आगामी तीन वर्ष के लिए योजनाओं पर चर्चा हेतु आहूत विधानसभा का विशेष सत्र अपने आप में एक अनूठी पहल मानी जायेगी जिसमें ज्यादातर चर्चा रचनात्मक हुई। संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीति से ऊपर उठते हुए यह भी रेखांकित किया कि प्रदेश के विकास में स्थापना से लेकर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं सबका कुछ न कुछ योगदान रहा है और उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। विजयवर्गीय का यह बताने का प्रयास सराहनीय माना जायेगा कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर यह माना कि विकास यात्रा में सभी पार्टियों व मुख्यमंत्रियों का योगदान रहा है। यह विशेष सत्र था इसलिए इसमें ज्यादातर सकारात्मक चर्चा ही हुई, लेकिन सामान्य सत्रों में भी यह अपने आप में एक उदाहरण बन सकता है ताकि जनहित के मुद्दों पर अधिक चर्चा हो सके। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई प्रस्तावों का स्वागत किया साथ ही यह मांग भी उठाई कि सरकार भले ही 2047 की योजनायें बनाये लेकिन 2026 की भी गारंटी दे। हमारे प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि दलगत राजनीति भले ही विविध विचारों को प्रश्रय देती हो लेकिन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को केवल जनहित देखना चाहिये और विपक्ष को उन मुद्दों पर केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए जो कि जनता के हित में हों। हालांकि विपक्ष का यह दायित्व भी है कि वह सरकार पर अंकुश रखे ताकि सरकार और नौकरशाही हावी ना हो पाये। चूंकि लोकतंत्र जनता के लिए होता है इसलिए जनहित को ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिलना चाहिए, यह केवल सकारात्मक राजनीति से ही संभव हो सकता है।

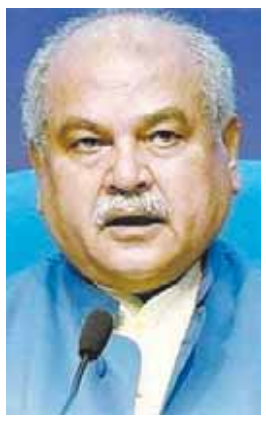

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने संकल्प प्रस्तुत करते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकतायें रेखांकित कीं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में रोजगार और युवा हैं तथा पांच साल में हम ढाई लाख सरकारी पद भरेंगे। जो भी गड़बड़ी करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर वनतारा

भी बनायेंगे। हमारे पास नेता, नीति और नियत है और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे। भले ही पिछले दो सालों में हमारे द्वारा किए गए काम अभी कम लगें लेकिन आगे यह मील का पत्थर साबित होंगे। प्रदेश की भाजपा सरकारों ने बीमारु कहे जाने वाले प्रदेश को विकासशील से विकसित राज्य की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लाल सलाम को भी प्रदेश ने आखिरी सलाम कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि लाड़ली बहना योजना कभी बन्द नहीं होगी। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटिन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। भोपाल के लिए भविष्य की राजधानी कैसी हो इस दिशा में काम कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटिन सिटी बनाने के साथ यह भी भरोसा दिलाया कि ग्वालियर और जबलपुर को 1926 में मेट्रापोलिटिन सिटी बनाने का काम हाथ में लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुनसिंह का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि नवोदय विद्यालय उन्होंने दिये जिन्होंने कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर जैसा कार्य कर किया।

और यह भी

संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय का अपना ही अंदाजेबयां है, उन्होंने प्रदेश के अब तक रहे 17 मुख्यमंत्रियों और उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की। रविशंकर शुक्ला से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक की कार्यशैली व उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। उनका कहना था कि शिवराज सिंह चौहान की योजनायें ऐसी रहीं जिनका पूरा देश नकल कर रहा है, चाहे लाड़ली बहना हो, चाहे लाड़ली लक्ष्मी हो, जननी एक्सप्रेस हो या सीएम कन्यादान योजना। महाकाल लोक व एकात्मधाम उन्हीं की देन है। कमलनाथ के बारे में उनका कहना था कि कमलनाथ में जबरदस्त प्रशासनिक क्षमता थी और उन्होंने ही औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सिंगल विन्डो योजना आरम्भ की, उनके पास बहुत सारी योजनायें थीं परन्तु समय कम था इसलिए वे उतना नहीं कर पाये। उमा भारती की सलाह पर ही एमपी आरडीसी का गठन किया गया, उसके बाद दस हजार करोड़ रुपये की सड़कें बनाई गयीं। भारी विरोध के बावजूद उमा ने हरसूद खाली कराया तब इंदिरा सागर बांध पहली बार भरा। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट और बाणसागर बांध उन्हीं के प्रयासों से बना। कोलार जल परियोजना में भी उन्हीं के प्रयास थे और दिग्विजय सिंह से राजनीतिक सौजन्यता सीखनी चाहिये। रवि शंकर शुक्ला ने नियोगी आयोग का गठन किया और प्रदेश में धर्मान्तरण रोकने की दिशा में कदम बढ़ाये। कैलाश नाथ काटजू ने वल्लभ भवन का निर्माण कराया। गोविंदनारायण सिंह ने रीवा में एपीसी यूनिवर्सिटी और विंध्य क्षेत्र में बाणसागर बांध को मंजूरी दिलाई। राजा नरेश चंद्र प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। श्यामाचरण शुक्ला ने प्रदेश में शहरीकरण को बढ़ावा दिया। प्रकाश चंद्र सेठी ने चंबल में डकैतों के आत्मसमर्पण की पहल की जबकि कैलाश जोशी ने ग्रामीण विकास की नींव रखी। वीरेंद्र कुमार सखलेचा ने नर्मदा घाटी विकास को आगे बढ़ाया। अर्जुनसिंह ने कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा दिया जबकि मोतीलाल वोरा ने संवेदनशील और मेहनती प्रशासन दिया। सुंदरलाल पटवा और बाबूलाल गौर ने अतिक्रमण हटाने की पहल की।

आवारा कुत्तों से हाई कोर्ट नाराज, निगम को निर्देश, 12 जनवरी तक स्थिति सुधारें

निगम के 2.39 लाख नसबंदी के दावे को भी हाई कोर्ट ने स्कैम बताया

इंदौर। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर नगर निगम को जमकर फटकार लगाई। आवारा कुत्तों से जनता की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान जब नगर निगम की तरफ से पक्ष रखा गया कि हमने 2 लाख 39 हजार से अधिक स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी कर दी और यह काम हर दिन जारी है।

इस पर कोर्ट ने निगम के वकील को रोकते हुए कहा कि देखिए यह नसबंदी करना और आंकड़े बताना एक बहुत बड़ा घोटाला है। हम खुद वॉक करने निकलते हैं तो जगह-जगह आवारा श्वान नजर आते हैं। हाई कोर्ट के प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस बीके द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि छप्पन दुकान, सराफा, एमजी रोड कहीं भी चले जाइए, आवारा कुत्ते बैठे मिल जाएंगे। कॉलोनी में बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे खेल नहीं पाते, साइकिल नहीं चला पाते। उनका सामाजिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। आप इस समस्या पर ठोस कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम नसबंदी अभियान और अब तक किए स्टरलाइजेशन के मामले में न्यायिक

जांच बैठा देंगे।

नगर निगम ने जब कहा कि शहर में दो स्थानों पर कैंप चल रहे हैं। अब तक 2 लाख 39 हजार की नसबंदी कर दी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह तो कागजों में होगा, आपके पास इसका क्या सबूत क्या है! असलियत तो शहर में नजर आ रही, पैदल चलना मुश्किल है। निगम के वकील ने कहा कि जहां से भी सूचना आती है, वहां से श्वानों को उठाकर रैबीज इंजेक्शन लगाते हैं और नसबंदी करते हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर रात में निकलना मुश्किल है। बाइक, स्कूटर वाले टकरा रहे हैं। कुत्तों के झुंड हमला कर रहे हैं। इस पर निगम ने आश्वासन दिया कि हम और तेजी और सख्ती से अभियान चलाएंगे।

इंदौर आवारा कुत्तों का हब

जस्टिस शुक्ला ने निगम द्वारा कुछ नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आप लोग 2 हजार रुपए एक श्वान के लिए खर्च कर रहे हो, यह वास्तव में बड़ा स्कैम है। इंदौर आवारा कुत्तों का हब बनता जा रहा है। हमने 25 नवंबर को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। कहीं कोई अभियान ही नहीं चलाया गया।

12 जनवरी से पहले हटाना होगा

इस मामले की सुनवाई अब 12 जनवरी को होगी। इससे पहले नगर निगम को प्रमुख स्थानों से आवारा श्वानों को हटाना होगा। हाई कोर्ट ने मामले में सीनियर एडवोकेट पीयूष माथुर को न्यायमित्र नियुक्त किया है। अधिवक्ता मनीष यादव भी इंटर विनर के रूप में पैरवी कर रहे हैं। जस्टिस द्विवेदी ने कहा, पूरे शहर में हर घर के आसपास कुत्ते बैठे रहते हैं। जब आप 2 लाख 39 हजार की नसबंदी कर चुके हैं फिर संख्या घटने के बजाय बढ़ क्यों रही है।

यहां भी लापरवाही हो रही

निगम नसबंदी करने, रैबीज इंजेक्शन लगाने के लिए कुत्तों को उठाकर ले जाता है, फिर दूसरी कॉलोनी में छोड़ जाता है। सिल्वर ऑक्स, चाणक्यपुरी, देवेंद्र नगर में आवारा कुत्तों की संख्या 40 के करीब हो गई है। हर 4-5 दिन में नए-नए श्वान यहां आ जाते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को रोजाना ये काट भी रहे हैं।

कॉलेज प्रशासन को एक गुमनाम पत्र से यह शिकायत मिली

एक महीने में दूसरी बार एमजीएम कॉलेज में रैगिंग होने की शिकायत

इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज एक बार फिर रैगिंग के गंभीर आरोपों को लेकर विवादों में घिर गया है। कॉलेज में रैगिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक माह के भीतर दूसरी शिकायत सामने आने से न केवल कॉलेज प्रशासन बल्कि मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए।

जूनियर छात्रों ने दूसरे मामले में आरोप लगाया कि 2024 बैच के सीनियर छात्रों ने 2025 बैच के विद्यार्थियों को एक निजी फ्लैट में बुलाया, जहां उनके साथ मारपीट की गई, डराया-धमकाया गया और जबरन शराब पिलाई गई। शिकायत कॉलेज प्रशासन को एक गुमनाम पत्र के माध्यम से दी गई। इसके बाद एंटी-रैगिंग कमेटी ने जांच शुरू की। जांच में आरोपों की पुष्टि होने से मामला और गंभीर हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना से जूनियर छात्रों में भारी दहशत है। शिकायत के अनुसार, छात्रों को नाचने के लिए मजबूर किया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़ितों में इंदौर के एक विख्यात डॉक्टर का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है।

जांच में यह भी सामने आया है कि जिन दो सीनियर छात्रों के नाम इस मामले में आए हैं, वे 18 नवंबर को हुई रैगिंग की घटना में भी शामिल थे, जिन पर उस समय एक माह का निलंबन लगाया गया था। कॉलेज डीन डॉ अरविंद घनघोरिया ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि सभी आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में खेल गतिविधियों के दौरान भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की एक अन्य शिकायत सामने आई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धोखे से बुजुर्ग को लगाया 1.83 लाख का चूना, साइबर ठगी का अनोखा मामला

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले साले के नाम से फोन करके ठगी की वारदात

इंदौर। रिश्तों का सहारा लेकर साइबर ठगों ने 82 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया। उनसे 1 लाख 83 हजार रुपये की ऑनलाइन ठग लिए। तुकोगंज थाना क्षेत्र की कंचन बाग कॉलोनी में रहने वाले जसवंत कुमार गुम्बर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

ठगे गए पीड़ित जसवंत कुमार गुम्बर की पीथमपुर में ट्यूब बनाने की फैक्ट्री है। पुलिस के अनुसार 24 नवंबर को उन्हें एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को उनका साला पिंटू बताया, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कॉलर ने पासपोर्ट और वीजा से जुड़े काम के लिए तत्काल पैसों की जरूरत बताई और एजेंट को भुगतान करने को कहा।

कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को एजेंट बताते हुए कॉल किया। भरोसे में आकर बुजुर्ग ने बताए गए खाते में 1.83 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्होंने अपने साले पिंटू को फोन किया, तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पिंटू ने न तो कोई कॉल किया था और न पैसों की मांग की। ठगी का एहसास होते ही बुजुर्ग ने साइबर सेल भोपाल में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने जीरो पर प्रकरण कायम कर केस डायरी इंदौर भेज दी। इसके आधार पर तुकोगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

सतर्क रहने की अपील

पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि विदेश से आए या परिचित की आवाज में आए किसी भी कॉल पर तुरंत भरोसा न करें और पैसों के लेन-देन से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे पुष्टि जरूर करें।

पुलिस का सख्त सुरक्षा अभियान, होटल और ढाबों की सर्चिंग की

संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, दस्तावेजों का सत्यापन किया

इंदौर। शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जोन-02 क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर यह अभियान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह के नेतृत्व में तथा पुलिस उपायुक्त जोन-02 कुमार प्रतीक और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।

अभियान के तहत जोन-02 क्षेत्रांतर्गत कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी छोटे-बड़े होटल एवं ढाबों में विशेष सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं नियमों के पालन की गहन जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही प्रत्येक थाना क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जनसंवाद एवं मोहल्ला मीटिंग का आयोजन किया गया। इन बैठकों में नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और स्थानीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई तथा सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाई गई। जोन-02 में निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की गई, वहीं संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस की सक्रिय उपस्थिति का संदेश दिया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि शहर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

रोबोटिक्स ने बदली स्कूल की तस्वीर

इंदौर। बदलते दौर में शिक्षा अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रही है। इंदौर के कुम्हार खेड़ी क्षेत्र में स्थित एमकेवीवी स्कूल ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक तकनीकी शिक्षा बड़े और महंगे स्कूलों की बपौती नहीं है। सीमित संसाधनों वाले इस प्राइवेट एमपी बोर्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर शिक्षा की नई तस्वीर पेश की।

करीब 19 वर्ष पूर्व स्थापित यह स्कूल बीते 10 वर्षों से रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। शुरुआती कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को रोबोटिक्स से जोड़ने का परिणाम यह है कि आज यहां के छात्र स्वयं ह्यूमनोइड रोबोट,एआई आधारित एप्लिकेशन, ड्रोन और 3डी प्रिंटेड मशीन पार्ट्स तैयार कर रहे हैं। विद्यालय संचालक विनय तिवारी (एमसीए) ने कहा कि तकनीकी रूप से सक्षम युवा ही देश के भविष्य की मजबूत नींव हैं। उनका उद्देश्य है कि एमकेवीवी स्कूल के विद्यार्थी 'मेक इन इंडिया' को साकार करें।

मामूली टक्कर बनी हिंसक झड़प, बेटे के सामने पिता की पिटाई की

टक्कर विवाद का वीडियो वायरल, दोनों पक्षों पर क्रॉस केस

इंदौर। हीरा नगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में सड़क पर हुई मामूली टक्कर के बाद हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

घटना पिछले दिनों की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, सुखलिया क्षेत्र में दो बाइक आपस में टकरा गई थीं, जिसके बाद मनोज पुरी और सागर वामदले के बीच कहासुनी शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट हो गई, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को उसके नाबालिग बेटे के सामने जमीन पर पटक-पटक कर पीटते नजर आ रहे हैं।

पीड़ित मनोज पुरी ने पुलिस को बताया कि वे अपने बेटे को परीक्षा के चलते स्कूल से लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक टर्न करने की बात को लेकर सागर वामदले और उसके साथी अनुज दीक्षित ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लोहे के पाइप से हमला किया गया, जिससे उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि पहले गालियां दी गई और मारपीट की शुरुआत मनोज ने की। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार, वीडियो फुटेज के आधार पर जांच जारी है और हीरा नगर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज किया है।

संपादकीय

बांग्लादेश चाहता क्या है?

पड़ोसी बांग्लादेश में शुक्रवार को हुई भारी हिंसा, एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के और हर घटना को भारत के खिलाफ मोड़ देने की साजिश के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश भारत से चाहता क्या है? भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव तो पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और भारत द्वारा उन्हें शरण दिए जाने के बाद से ही वहां कट्टरपंथी भारत के खिलाफ लगातार आग उगलने का काम करते रहे हैं। अब इसमें नई चिंगारी भारत पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से अलग करने की है। बांग्लादेश की आंतरिक हालात बेहद खराब है और वहां फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में भारत एक अहम मुद्दा है। हालत है कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और देश भर में उसके सहायक उच्चायोगों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और सेना उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। अब भारत के लिए यह मायने रखता है कि बांग्लादेश में फ़रवरी में होने वाले चुनाव में किसे जीत मिलती है। भारत को लेकर हालिया नाराज़गी 12 दिसंबर को 32 वर्षीय शरीफ़ उस्मान हादी को गोली मारकर हत्या से भड़की। हत्यारे अभी भी फरार है। इस बीच बांग्लादेश में यह अफवाह फैलाई गई कि हत्यारों को भारत ने शरण दे रखी है। गौरतलब है कि भारत विरोधी हादी को पिछले शुक्रवार ढाका में बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। तब हादी 12 फ़रवरी को होने वाले चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर रहा था। इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई थी। बांग्लादेश के चुनाव में कौन जीतता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। चूंकि वहां पूर्व में सत्तासीन अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, इसलिए चुनाव निष्पक्ष तो वैसे भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अवामी लीग अभी भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दूसरी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) है, जो सत्ता की दावेदार हैं। हालांकि उसके भी भारत के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। दूसरे, इस पार्टी की नेता और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा ज़िया गंभीर रूप से बीमार हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारा खालिदा जिया की सेहत की दुआ के बाद माना जा रहा था कि बीएनपी सत्ता में आए तो बांग्लादेश से रिश्ते कुछ सुधर सकते हैं। हालांकि बीएनपी भी कट्टरपंथी पार्टी मानी जाती है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और देश में बहुदलीय लोकतंत्र की समर्थक रही हैं। लेकिन पिछले तीन चुनावों का बीएनपी ने बहिष्कार किया है। भारत की पूर्व विदेश सचिव निरूपमा राव मानती हैं कि अगर शेख हसीना सत्ता में होतीं तो बांग्लादेश जिस रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है, वैसा नहीं होता। हसीना कोई क्रांतिकारी नहीं थीं बल्कि एक शत्रुतापूर्ण माहौल में देश-निर्माता थीं। एक स्थिर शक्ति थीं। उन्होंने जमात और उसके सहयोगी संगठनों को नियंत्रण में रखा। नागरिक-सैन्य संतुलन बनाए रखा। किसी भी यथार्थवादी विकल्प की तुलना में अल्पसंख्यकों की बेहतर सुरक्षा की और बांग्लादेश को आर्थिक के साथ भू-राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखा। हसीना पर दबाव बढ़ाने से लोकतंत्र स्वतः ताकतें सशक्त नहीं हुईं। इसके बजाय सड़क की ताकत, कट्टरपंथी तत्व और लोग मज़बूत हुए जो संस्थाओं के कमज़ोर पड़ते ही फलते-फूलते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अब जो हो रहा है, वह कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी और ऐसे ही संगठनों को सत्ता में लाने की साजिश ज्यादा लग रही है। दुख की बात यह है कि बांग्लादेश के लोगों ने इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते भारत के सारे अहसानों को भुला दिया है। ऐसे में आगे बांग्लादेश पर भरोसा करना भारत के लिए खतरे से खाली नहीं होगा।

सामाजिक भेद मिटाने, नारे नहीं नीयत जरूरी

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक लोहियावादी विचारक हैं।

अजाक्स के प्रादेशिक सम्मेलन में उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा के विवादास्पद भाषण को लेकर प्रदेश व प्रदेश के बाहर भी बहस जारी है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि श्री संतोष वर्मा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह न तार्किक, न संवैधानिक न व्यावहारिक और ना ही नीतिगत है। उनके भाषण के उस अंश को मैं चूंकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश से बाहर था अतः ठीक से विवरण सहित नहीं पढ़ सका और न सुन सका था। अपने साथियों से मैंने उनके विवरण का वह अंश मंगाया और उसे ठीक से सुना और अब मैं अपने विचार को ठीक ढंग से व्यक्त कर सकता हूं।

यह हो सकता है कि अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित होने के बाद श्री संतोष वर्मा अति उत्साह में ऐसे शब्द बोल गए हों, हालांकि बाद में उन्होंने इसका खंडन भी किया और यह सफाई भी दी कि अगर मेरे कहने से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, उन्होंने अपने भाषण में जो बिंदु कहे और मैंने सुने वह निम्नानुसार हैं-

1. जो लोग पदोन्नति में आरक्षण का एक पीढ़ी के बाद विरोध करते हैं, वह इस आधार पर कि अब आरक्षण प्राप्त व्यक्ति आर्थिक रूप से समर्थ हो चुके हैं और आरक्षण के अधिकारी नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक की कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को मेरे बेटे को दान न कर दे या उससे संबंध ना बना ले।

2. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जातिवाद और भेदभाव मिट जाए तो मैं आरक्षण की बात नहीं करूंगा। उनके इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई जो की स्वाभाविक भी हैं। ब्राह्मण समाज के कुछ प्रवक्ताओं को श्री संतोष वर्मा को उत्तर देने का कुछ आधार मिल गया है, यह भी तथ्य है कि ब्राह्मण समाज उस अर्थ में ज्यादा संगठित और कुछ आक्रमक भी है।

श्री संतोष वर्मा के भाषण को मैं निम्न आधार पर उचित नहीं मानता हूं।

1. भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार को पिछड़ेपन का आधार माना गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान निर्माण के काफी पहले 1930 के दशक में आरक्षण महात्मा गांधी की पहल पर स्वीकृत हो चुका था। उस समय अनुसूचित जातियों में मुख्यतः वह जातियां थी जो अस्पृश्य थी, परंतु संविधान निर्माण के बाद अभी तक संविधान संशोधन और कानून के द्वारा अनेकों ऐसी जातियों को सूची में शामिल किया गया है जो अस्पृश्य नहीं है। यद्यपि सामाजिक व शैक्षणिक आधार की कसौटी पर वह नीचे के पायदान पर रही हैं। जहां तक पदोन्नति में आरक्षण का सवाल है तो श्री संतोष वर्मा का कथन नितांत अनुचित है और बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो अनुसूचित जाति के शिक्षित और संपन्न या ताकतवर तबके के द्वारा अनुसूचित जाति के भाइयों का ही शोषण है। जब किसी परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल जाता है और वह किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं रहता। वह उस अर्थ में अस्पृश्य भी नहीं रहता जिस अर्थ में अस्पृश्यता को अनुसूचित जाति का मूल आधार माना गया था और अगर उसके परिवार को यानी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो वह आरक्षित पद उस अनुसूचित जाति के ही किसी अन्य व्यक्ति के हक में जाएगा जिसे एक बार भी आरक्षण का लाभ या अवसर नहीं मिला। मैं अनुसूचित जाति व जनजाति के अनेकों ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके घर में एक से अधिक आईएएस/आईपीएस हैं, क्योंकि एक अवसर मिला और उससे उन्हें जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास का अवसर मिला उससे उन्हें और उनके परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। अब भले ही वह जन्मना उस अनुसूचित जाति में जन्म लिये हो परंतु वे अब अपनी ही जाति के उन लोगों से बहुत आगे हैं जो आज भी शिक्षा, सुविधाओं और साधनों से वंचित है।

1. मैं अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति को आरक्षण सूची से हटाने की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि इन जातियों के समर्थ लोगों को स्वतः ही अपने असमर्थ भाइयों के लिए त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। यह विचित्र है कि जो लोग दूसरे समर्थ लोगों से अपने लिए आरक्षण या विशेष अवसर चाहते हैं परंतु स्वयं समर्थ होने पर अपने ही भाइयों को, सजातीय भाईयों को वह त्याग करने को तैयार नहीं है। जहां तक आरक्षण का प्रश्न है वह आर्थिक विकास या रोजगार के लिए नहीं है बल्कि सामाजिक बराबरी और सहभागिता के लिए है। जो लोग आरक्षण का लाभ मिलने से बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं उन्हें व्यक्ति के तौर पर सहभागिता और बराबरी काफी हद तक मिल जाती है। मैं उस नीति का पक्षधर हूं कि एक व्यक्ति को राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था में आरक्षण का लाभ एक बार मिल जाने के बाद उसकी दूसरी पीढ़ी को उसका लाभ नहीं देना चाहिए बल्कि उनकी ही जातियों के वंचित लोगों को लाभ देना चाहिए जिन्हें एक बार भी अवसर नहीं मिला। राजनीतिक क्षेत्र में ज्ञानी जैल सिंह, श्री राम विलास पासवान, श्री बूटा सिंह, सुश्री मायावती और ऐसे कितने ही अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के राजनीतिक परिवारों का उल्लेख किया जा सकता है, जो मेरी राय में आरक्षण के लाभ के अब पात्र नहीं हैं। अब ऐसे लोग आरक्षण का लाभ लेकर अपनी ही जाति व वंचित समुदाय के लोगों के अवसरों को छीन रहे हैं।

2. यह अक्सर देखा गया है कि आरक्षित समुदाय के लोग आरक्षण का लाभ उठाकर बड़े पदों पर पहुंचे, अपनी दलित पत्नियों या उनकी लाचारी का लाभ उठाकर उनके जीते जी दूसरी शादियां सवर्ण लड़कियों से अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर लेते हैं इस पर क्या दलित व पिछड़े समुदाय को नहीं सोचना चाहिए? जो अपने पद व प्रतिष्ठा के बल पर अपनी ही जाति की अशिक्षित या उस अर्थ में असुंदर महिलाओं को छोड़कर अपनी भोग विलासता के लिए दूसरी शादी सुंदरता और अन्य आधारों पर करते हैं क्या वह अपनी जाति के साथ अन्याय नहीं करते? क्या ऐसे लोगों को अनुसूचित या पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए? यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और वर्तमान में न्याय संहिता की धारा के तहत एक पत्नी के रहते और बगैर उसकी अनुमति के बहु विवाह अपराध है परंतु वे गरीब व कमजोर परिवार की महिलाएं या उनके परिवार के लोग अफसरी या सत्ता की चमक दमक के आगे बोल नहीं पाते और बेचारी गांव में पड़ी-पड़ी मौत की शिकार हो जाती हैं। वे अपनी परंपराओं, कट्टरताओं के चलते अपने पति के विरुद्ध रिपोर्ट भी नहीं करती और न पैसे आदि की मांग करती है।

3. श्री संतोष वर्मा का यह कथन है कि तब तक आरक्षण रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को अनुसूचित जाति वालों को दान नहीं करते विचित्र और अनुचित है। अंतर जातियां शादियां हों या अनुलोम विलोम हो, यानी ऊपर शीर्ष वाले लोगों की नीचे वालों से शादी हो यह अच्छा है परतु शादी तो स्वेच्छा से ही होगी बाध्यता तो बलात्कार जैसा अपराध होगा। एक जाति के भीतर भी और न्यायपालिका के कई निर्णयों के अनुसार पति-पत्नी के बीच संबंध स्वेच्छा के आधार पर ही होंगे नहीं तो वह बलात्कार की श्रेणी में ही आएंगे। अनेकों ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जहां पर सवर्ण समाज या ब्राह्मण लड़कियों ने अनुसूचित जाति के लड़कों से शादी की है। स्वर्गीय पुखराज मारू की दूसरी शादी एक ब्राह्मण की बेटी से स्वेच्छा से हुई। अगर शादी-विवाह स्वेच्छा से होंगे तो इस पर कोई भी समाज आपत्ति नहीं करेगा और अगर करेगा तो कानून के अनुसार दंड का भागीदार होगा।

हालांकि हमारा भारतीय समाज इतना जटिल व क्रूर है कि अक्सर समाचार पत्रों में अंतर जाति, अंतरधर्मी शादी के करने के अपराध में परिवार वाले ही अपने बेटे बेटियों की हत्या कर देते हैं और जिसे मीडिया श्ऑनर किलिंग्य कहता है हाँलाकि यह ऑनर किलिंग नहीं है बल्कि व्यक्ति व संविधान की क्रूर हत्या है।

4. मुझे ऐसे भी कितने प्रकरणों की जानकारी है जहां सवर्ण समाज के लोगों ने अपनी बेटियों को आरक्षित वर्ग में नौकरी पाने के लिए बाकायदा लेन देन कर पंजीकृत शादियां कर दी जो केवल कागजों में थी और नौकरी लग जाने के बाद उन शादियों को तोड़ दिया। अब यह तो ब्राह्मण या सवर्ण कन्याओं का लिखित स्वेच्छिक दान था तो क्या इस आधार पर श्री संतोष वर्मा आरक्षण समाप्ति की मांग करेंगे।

ब्राह्मण समाज की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियायें हो रही है और अब श्री संतोष वर्मा के प्रशासनिक इतिहास के कई किस्से सही या गलत, जैसे उन्होंने कोर्ट से बरी होने को झूठा दस्तावेज दिया था, या किसी महिला का शारीरिक शोषण किया था आदि आदि। यह सब सोशल मीडिया पर निकलकर आ रहे हैं। इनमें कितने आरोप सही है या गलत हैं मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कि सही हो या प्रतिक्रिया हो। परंतु सामाजिक वातावरण में एक मानसिक कटुता रूपी पूर्ण विभाजन हो गया है और ब्राह्मण समाज की ओर से भी अब अनेकों ऐसे अतार्किक तर्क दिए जा रहे हैं जो गैर जरूरी है, जैसे नामकरण हम करते हैं, तर्पण हम कराते हैं, तो तेरहवीं भी हम कराएंगे, आदि आदि। मैं इनकी विवेचना या बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। समाज में जन्मना छोटे-बड़े का भेदभाव खत्म हो, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। श्री संतोष वर्मा का कहना कि श्जातिवाद भेदभाव समाप्त करें तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे्य यह एक निरर्थक जुमला है। उनकी बात केवल शाब्दिक भाषण बाजी है। जातिवाद कौन मिटाएगा? जातिवाद कोई सरकार या व्यवस्था अकेले नहीं मिटा सकती, वह कुछ कड़े कानून बना सकती है परंतु अंततः तो समाज के मन को ही बदलना होगा। अपने मन से यह स्वीकार करें कि जातिवाद और जाति अब दोनों ही अप्रसांगिक और निरर्थक हो चुकी है। मानव मानव एक जाति है। जैसा कि कबीर ने कहा था कि (जो कछु तुर्की तुर्क जाया, काहे ना पेटे खमन कटाया, जो कहु बम्हनी बामन जाया काहे ना पेटे जनेऊ चढ़ाया।) हम इंसान सब एक से व समान पैदा होते हैं और उनमें असमानता खोजना या छुआछूत, छोटे-बड़े का भेदभाव करना यह तो ईश्वर विरोधी कर्तव्य है। जातिवाद सवर्ण और अवर्ण के बीच है, तो अवर्ण जातियों के बीच भी गहरा भेद व असमानता तथा भेदभाव का व्यवहार है। क्या आमतौर पर वाल्मीकि समाज व चर्मकार समाज, नाई, धोबी व तेली समाज में आपस में, सोच समझकर या परिवार की राय से आमतौर पर शादी विवाह करते हैं? कोई स्वेच्छा से कर ले तो वह अपवाद ही है। इसलिए,भले ही जातिवाद के जनक ब्राह्मण रहे हों, परंतु अब जातिवाद को मिटाने का ठेका उन्हीं को देने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और सवर्ण सभी को प्रयास करना चाहिए कि जातिवाद व भेदभाव समाप्त किया जाए।

भय पैदा करने वाली घटनायें

राजनीति

अवधेश कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इस तस्वीर की हममें से शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि बाबरी मस्जिद की कहीं नींव डाली जाएगी और उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा से सटे इलाके में भीड़ के सामने प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद की नींव रख दी। हुमायूं कबीर पश्चिम मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं। अचंभे की बात है कि हुमायूं कबीर लंबे समय से सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे थे कि वह 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करेंगे। इस कारण पश्चिम बंगाल के अंदर और समूचे देश में तनाव और असहजता का वायुमंडल कायम हो रहा था। अलग-अलग मंचों से इसे रोकने की मांग भी की गई। किंतु अंततः हुमायूं कबीर ने बिना किसी रोक-टोक के हजारों मुसलमानों को इकट्ठा किया और पूरा वातावरण ऐसा था कि कोई रोकने जाता तो उसकी शामत आ जाती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। केवल तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। क्या ऐसे व्यक्ति को निलंबित करना ही पर्याप्त था?

कानून और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कोई भी राज्य इस तरह सांप्रदायिकता भड़काने और तनाव करने की योजना वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करता, हिरासत में लेता या कम से कम उसके घर में नजरबंद करता। इसके साथ ऐसे कार्यक्रम पर रोक भी लगाई जाती। मुर्शिदाबाद का दृश्य इसके विपरीत था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस उस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है। जब पुलिस प्रशासन को राजनीतिक नेतृत्व से रोकने का कोई आदेश नहीं था तो वह ऐसी ही भूमिका निभाएग? किसी को भी कानूनी रूप से वैध जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है। बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनाना करोड़ हिंदुओं सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना और जख्मों को कुरेदना है जो हर दृष्टि से अस्वीकार्य है। 1529 में बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद निर्माण के विरुद्ध वर्षों का संघर्ष अब सबको पता है। अंततः स्वतंत्रता के बाद आंदोलन और फिर आगे न्यायिक संघर्ष से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर निर्माण किया गया। बावजूद देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि बाबर के साथ उसका जुड़ाव है, उससे प्रेरणा मिलती है और इसलिए मस्जिद हमें बनानी है तो यह भारत की एकता -अखंडता- सांप्रदायिक सद्भाव और भविष्य की दृष्टि से डरावना संकेत है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस बाबर को उसके मूल स्थान उज़्बेकिस्तान में महत्व नहीं मिलता और वहां उसे लूटेरा तक बोला जाता है भारतीय मुसलमान स्वयं को उससे जोड़ते हैं।

यह अभियान यहीं रुकने वाला नहीं दिखता। तहरीक मुस्लिम शब्बन नामक संगठन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेल्फेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का ऐलान किया है। पता नहीं आगे कौन कहां बाबर के नाम पर और कुछ निर्माण की घोषणा कर दे। विडंबना देखिए कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश में मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दिया है। अनेक मुस्लिम नेताओं ने घोषित कर दिया कि उन्हें वह जमीन नहीं चाहिए। बेलडांगा की तस्वीर देखकर किसी को अगर डर पैदा नहीं होता तो साफ है कि वह इतिहास एवं वर्तमान दोनों से सीख लेने को तैयार नहीं है । भारत विभाजन के पीछे बंगाल वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप से कट्टरपंथियों के लिए बहुत बड़ी ताकत बना था। 16 अगस्त, 1946 को डायरेक्ट एक्शन दे यही हुआ था जिसमें सैंकड़ों हिंदुओं को सरेआम काटा गया महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ हुए ताकि गैर मुस्लिम डर जाएं ,कांग्रेस दबाव में आए एवं ब्रिटिश सरकार के सामने मुसलमानों के लिए अलग देश देने के अलावा चारा न बचे। आज बंगाल के अलावा भी देश में किसी ने किसी रूप में डायरेक्ट एक्शन दे चल रहा है। आखिर हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिम समुदाय के इतने लोगों का खड़ा होना, कई करोड़ रूपया देना, माथे पर ईंट लेकर चलना, खतरनाक नारे लगाना तथा लगातार धन भेजते रहने का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? समारोह स्थल पर 'नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर' के साथ हिंसक नारे भी लग रहे थे। पुलिस प्रशासन रोकने की औपचारिक भी नहीं निभा सका।

कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख सकते हैं। हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इनमें 90 स्पष्ट मुस्लिम प्रभाव वाले तथा 45 अन्य सीटें हैं। विश्लेषण किया जा सकता है कि उससे क्या तृणमूल को चुनाव में क्षति होगी? यह प्रश्न केवल चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है देश के लिए डर पैदा होने वाली घटना है। अगर दो पार्टियां ही सही बाबर और फिर बाबरी मस्जिद के नाम पर मानती हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट मिल जाएगा तो इससे देश की स्थिति का अनुमान लगा लीजिए। ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम वोट खिसकने के डर से ही हुमायूं कबीर को रोकने का कदम नहीं उठाया। अगर इतने बड़े समुदाय में बाबर के नाम पर वोट मिलने या कटने की उम्मीद या भय है तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। हुमायूं कबीर की राजनीतिक पृष्ठभूमि सभी पार्टियों से है। पर उनकी सांप्रदायिक गैर मुस्लिम खासकर हिंदू विरोधी मानसिकता लंबे समय से सामने है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि, 'मुर्शिदाबाद में 70 फ़ीसदी जनसंख्या मुस्लिम है. बीजेपी के समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंगे।' मुर्शिदाबाद में भाजपा के समर्थक कौन लोग हैं किस समुदाय के लोग हैं?

पहले बंगाल के वामपंथी शासन और बाद ममता ने ऐसे खतरनाक कट्टर हिंसक शेर की सवारी की जो उनके लिए भी संकट बन रहा है और देश के लिए तो खैर भीषण समस्या हुआ ही है। अंदर की स्वाभाविक मजहबी कट्टरवादी सोच धीरे-धीरे सामने आने लगा। आज हम मुसलमानों के बड़े तपके को औरंगजेब, बाबर, गजनी स्वयं को गाजी घोषित करने वाले क्रूर हमलावरों के साथ सरेआम जोड़ते देख रहे हैं।

किसी भी समुदाय से उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इतिहास की कुछ बातें स्पष्ट हैं तो उन्हें स्वीकार कर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। भारत में सारे दृश्य इसके उलट हैं। मुसलमानों के शायद सबसे बड़े संगठन के मौलाना मदनी सरेआम कहते हैं कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। ध्यान रखिए उसके एक दिन पहले ही दिल्ली में डॉक्टर आतंकवादियों के समूह में से एक ने कार विस्फोट कर स्वयं को उड़ा लिया था। उसकी किसी संगठन ने स्वयं औपचारिक निंदा नहीं की। सीधा समर्थन न करते हुए किंतु परंतु के साथ सरकार एवं हिंदू संगठनों के व्यवहार को इसका कारण साबित करने की कोशिश की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले पर फैसले के बाद से किसी मुस्लिम संगठन के नेता ने इसे न्यायसंगत नहीं माना। फैसले को स्वीकार करने की जगह खुलेआम अपने को इस देश पर हमला करने, दूसरे पंथों, धर्म के स्थलों को ध्वस्त करने या उन पर मस्जिद या मजार आदि बनाने को इस्लामी मानता है तो उन्हें आप तथ्य और तर्कों से सहमत नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद की नींव के बाद देश को इस्लाम की स्वाभाविक कट्टरवाद के कटु यथार्थ समझना चाहिए और सरकार के साथ एक-एक व्यक्ति को तय करना चाहिए कि इनका मुकाबला कैसे करें। बंगाल और अन्य प्रदेश के मतदाता कम से कम अपने वोट से इसका विरोधकरें। मुस्लिम समुदाय के अंदर भी ऐसे लोगों हैं जो इस प्रकार के व्यवहार को उचित नहीं मानते और भारत की एकता अखंडता कायम रखना चाहते हैं। उन्हें भी आगे आकर विरोध करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि जिन्हें भारत में समस्या दिख रहा है वे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान आदि की स्थिति देख लें। वहां संघ तथा भाजपा नहीं है। यहां आप बहाने बना सकते हैं, उन देशों की हालत के लिए किस दोषी मानेंगे।

सोशल इन्फ्लुएंसर का प्रभाव की दिशा क्या

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखिका स्तंभकार हैं।

डिजिटल युग ने मनुष्य को अभिव्यक्ति की अभूतपूर्व स्वतंत्रता दी है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अनुभव और दृष्टिकोण को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। इसी परिवर्तन ने 'सोशल इन्फ्लुएंसर' नामक एक नई सामाजिक पहचान को जन्म दिया है। ये वे लोग हैं जिनकी बातों, जीवनशैली और विचारों का समाज, विशेषकर युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परंतु आज यह प्रश्न अत्यंत आवश्यक हो गया है कि सोशल इन्फ्लुएंसरों के कारण समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं। चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक,उनके लिए वास्तव में ज़िम्मेदार कौन है?

आरंभ में सोशल मीडिया का उद्देश्य संवाद, जागरूकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। कई इन्फ्लुएंसरों ने सच में समाज को दिशा देने का प्रयास किया। किसी ने शिक्षा को सरल और सुलभ बनाया, किसी ने स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और स्वच्छता जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाई, तो किसी ने भ्रष्टाचार, लैंगिक समानता और सामाजिक कुरीतियों पर साहसपूर्वक प्रश्न उठाए। ऐसे इन्फ्लुएंसर आज भी मौजूद हैं, जो देश और समाज के हित में ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं।

परंतु दुर्भाग्यवश, आज सोशल मीडिया पर एक बड़ी भीड़ ऐसी है जो समाज को बदलने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल पैसे और प्रसिद्धि के लिए इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। 'फॉलोअर्स', 'लाइक्स', 'व्यूज' और 'ब्रांड डील' ही सफलता के मापदंड बन गए हैं। कंटेंट की गुणवत्ता, सच्चाई और नैतिकता गौण होती जा रही है। वायरल होने की होड़ में कई बार भ्रामक जानकारी, दिखावटी जीवनशैली, अनैतिक व्यवहार और झूठे सपनों को परोसा जाता है।

इसका सबसे अधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। वे यह मानने लगते हैं कि सफलता बिना मेहनत, बिना संघर्ष और बिना धैर्य के मिल सकती है। वास्तविक जीवन की कठिनाइयों, परिश्रम और अनुशासन का महत्व कम होने लगता है। समाज में मूल्य-आधारित सोच के स्थान पर तात्कालिक लाभ और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

परंतु यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि सभी सोशल इन्फ्लुएंसर गलत या नकारात्मक नहीं होते। कई लोग सच में सामाजिक बदलाव, राष्ट्रहित और जनजागरण के लिए कार्य करना चाहते हैं। वे सच्चाई, ज्ञान और नैतिक मूल्यों के पक्ष में खड़े होते हैं। प्रश्न यह है कि ऐसे सकारात्मक और जिम्मेदार इन्फ्लुएंसरों को समाज से कितना समर्थन मिलता है?

अक्सर देखा जाता है कि गंभीर, सार्थक और समाजोपयोगी कंटेंट की अपेक्षा सनसनीखेज़, हल्के और दिखावटी कंटेंट को अधिक लोकप्रियता मिलती है। ऐसे में सच्ची आवाज़ें भीड़ में दब जाती हैं। यह स्वयं समाज के लिए एक प्रश्नचिह्न है। क्या हम सही लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं?

अब ज़िम्मेदारी के प्रश्न पर विचार आवश्यक है।

सबसे पहले ज़िम्मेदारी स्वयं इन्फ्लुएंसर की है। यदि किसी व्यक्ति को समाज प्रभावित करने की शक्ति मिली है, तो उसके साथ नैतिक उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। केवल पैसे और प्रसिद्धि के लिए भ्रामक या हानिकारक विचार फैलाना सामाजिक पतन को बढ़ावा देता है।

दूसरी ज़िम्मेदारी दर्शकों की है। हम जिसे देखते हैं, जिसे साझा करते हैं और जिसे लोकप्रिय बनाते हैं, वही आगे बढ़ता है। यदि दर्शक विवेकपूर्ण चयन करें और सकारात्मक, सचेत और समाजहितकारी कंटेंट को समर्थन दें, तो नकारात्मक इन्फ्लुएंसर स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाएँगे।

तीसरी ज़िम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है, जिन्हें केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही परिवार और शिक्षा व्यवस्था को बच्चों में आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों का विकास करना होगा।

आज हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, परंतु अधिकांश लोग समाज बदलने के लिए नहीं, बल्कि पैसे और प्रसिद्धि के लिए इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। पर साथ ही यह भी सत्य है कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाले इन्फ्लुएंसर आज भी मौजूद हैं, बस प्रश्न यह है कि हम उन्हें कितना पहचानते, स्वीकारते और समर्थन देते हैं।

जब उद्देश्य सही होगा और समर्थन भी सही दिशा में मिलेगा, तभी सोशल मीडिया समाज के पतन का नहीं, बल्कि उत्थान का माध्यम बन सकेगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

महिमा 'ज्ञाता दृष्टा भाव' को आत्मसात करने की

व्यंग्य

राजेंद्र बज

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मैंने अपने जीवन में 'ज्ञाता दृष्टा' भाव को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है। जिसके चलते अब मन अशांत नहीं होता, और न ही उच्च या निम्न रक्तचाप की शिकायत रहा करती है। हृदय की धड़कन विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य रूप में ही धड़का करती है। दिल और दिमाग पर किसी तरह का भी बोझ नहीं रहा है। जिसके चलते स्वभाव का चिड़चिड़ापन काफ़ूर हो चुका है। मन एकदम आनंद के महासागर में गहरी डुबकी लगाता रहता है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रही, एक प्रकार से जमाने के कदम ताल से मैंने कदम मिला लिए हैं। कल तक का बोझिल जीवन अब उन्मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुका है।

कुल मिलाकर जैसी भी है - वैसी जिंदगी को सही तरीके से जीने का मार्ग प्रशस्त होने लगा है। कब, कौन, कहां, क्या और कैसे कर रहा है ? ऐसे बेकार सवाल मन को अब उलझाते नहीं है ।दरअसल चतुर सुजान की नजरों में यह एक परम आध्यात्मिक अवस्था है, जो अंतर्मन में दिव्य आनंद की अनुभूति का संचार करने में सहायक होती है। वरना कल तक तो मै तमाम तरह की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर व्याप्त विसंगतियों को लेकर अपना खून जलाता ही रहता था। लेकिन अब बहुत ही शांत मन से जमाने में जमाने के दस्तूर को टकटकी लगाकर देखता ही रहा करता हूं। वह भी एकदम निस्पृह भाव से।

जमाने में काफी तब्दीली आ गई है, जिसे मैंने सच्चे मन से स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी से शिकायत नहीं करता। किसी से मन ही मन शिकायत नहीं रखता। यही नहीं अपितु जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने में ही अपनी खैर समझता हूं। सचमुच तमाम तरह की लाचारी और असहाय स्थिति से उबरने का यह 'आध्यात्मिक ज्ञान' मेरी आकुल व्याकुल मनःस्थिति से निजात दिला चुका है। यही नहीं बल्कि अब तो मै बात-बात पर खिलखिला कर हंसने भी लगा हूं। जान-पहचान वाले तो मेरे उन्मुक्त ठहाकों को लेकर आश्चर्यचकित रहा करते हैं। सोचते होंगे कि आखिर यह शख्स किस मिट्टी का बना हुआ है !

यकीन मानिए, कल तक जो चिंताएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी, वह आपसे पीछा छुड़ा लेगी। और हम भी उन्मुक्त जीवन जी सकेंगे। बशर्ते कि हम 'ज्ञाता दृष्टा' भाव के आध्यात्मिक जीवन दर्शन को आत्मसात कर लेवे। वैसे भी हम आजकल के बिगड़े हुए हालातो को नहीं बदल सकते। हकीकत तो यह है कि ऐसी हर कोई कोशिश हमको मुख्यधारा के विपरीत सिद्ध कर सकती है। जिन्होंने आज के दौर में होश संभाला है, उनकी नजरों में तो आप सर्वथा अप्रासंगिक करार दिए जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि समय की धारा के प्रवाह में बह लिया जाए। अन्यथा जिंदगी में सिवाय कूढ़-कूढ़ और किच-किच के और कुछ शेष नहीं रहेगा।

कुछ शख्सियत ऐसा मानती है कि वर्तमान दौर तो फिर भी अच्छा है, लेकिन आने वाला दौर आजकल के दौर से और भी अधिक बुरा होगा। इसलिए यही अच्छी बात है कि आज का जमाना जैसा है उसको उसी के अनुरूप जी लिया जाएं। चतुर सुजान यह भी फरमाते हैं कि जब जिंदगी बुरी तरह उलझ जाएं, कहीं से कहीं तक सुलझने के असर ही नहीं हो, तो अपने आप को हालात के हवाले कर दिया जाना चाहिए। इस गणित को और अधिक स्पष्ट करते हुए चतुर सुजान यह भी फरमाते हैं कि जिस प्रकार गोल-गोल आड़ी टेढ़ी जलेबी आड़ी तिरछी होने का गम नहीं मानती और चासनी में डूब कर चासनी का आनंद लिया करती है, हमें भी कुछ इसी तर्ज पर चलने की जरूरत है।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

अवमानना की शक्ति व्यक्तिगत कवच नहीं

अपनी गलती के लिए पछतावा स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए और गलती करने वाले को माफ करने के लिए इससे भी बड़ा गुण चाहिए। इसलिए दया न्यायिक विवेक का एक जरूरी हिस्सा बनी रहनी चाहिए। इसे तब दिखाया जाना चाहिए, जब अवमानना करने वाला ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करता है और उसके लिए प्रायश्चित करना चाहता है।

न्यायालय की अवमानना के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में इस बात पर जोर दिया कि अवमानना के लिए सजा देने की शक्ति आलोचकों को चुप कराने या न्यायाधीशों को जांच से बचाने का कोई जरिया नहीं है। साथ ही यह घोषणा भी की कि अवमानना का अधिकार क्षेत्र कभी भी न्यायपालिका के लिए व्यक्तिगत कवच नहीं बनना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सजा देने के अधिकार में माफ करने की शक्ति भी शामिल होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई अवमानना करने वाला व्यक्ति सच्ची पछतावा दिखाता है तो दया न्यायिक विवेक का मुख्य हिस्सा बनी रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि सजा देने की शक्ति में स्वाभाविक रूप से माफ करने की शक्ति भी शामिल होती है। जब न्यायालय के सामने मौजूद व्यक्ति उस काम के लिए सच्ची पछतावा और पश्चाताप दिखाता है, जिसकी वजह से वह इस स्थिति में आया है तो अवमानना के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह शक्ति न्यायाधीशों के लिए व्यक्तिगत कवच नहीं है और न ही आलोचना को चुप कराने की तलवार है। आखिरकार अपनी गलती के लिए पछतावा स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए और गलती करने वाले को माफ करने के लिए इससे भी बड़ा गुण चाहिए। इसलिए दया न्यायिक विवेक का एक जरूरी हिस्सा बनी रहनी चाहिए। इसे तब दिखाया जाना चाहिए, जब अवमानना करने वाला ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करता है और उसके लिए प्रायश्चित करना चाहता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियां बॉम्बे उच्च न्यायालय का एक आदेश रद्द करते हुए की। इसमें विनीता श्रीनंदन को एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों से जुड़े विवाद के संदर्भ में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां वाले परिपत्र जारी करने के लिए एक हफ्ते की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इस बात से सहमत था कि परिपत्र अवमानना वाला था और न्यायालय की बदनामी करने में सक्षम था। लेकिन, उसने माना कि उच्च न्यायालय ने श्रीनंदन की बिना शर्त माफी को स्वीकार न करके गलती की। खंडपीठ ने कहा कि वह पहले मौके पर पेश हुई, पछतावा जाहिर किया और माफी मांगी, जो अवमानना अधिनियम की धारा 12 की जरूरतों को पूरा करती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय का पहले के अवमानना के फैसलों पर भरोसा करना गलत था। उन मामलों में ज्यादा गंभीर आरोप या ऐसी स्थितियां शामिल थीं, जहां अवमानना करने वाले ने बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी। यहां, तथ्यों का मामला काफी अलग था। कानूनी योजना के तहत न्यायालय को सच्ची पछतावा दिखाए जाने पर सजा कम करने पर विचार करना जरूरी था। यह दोहराते हुए कि अवमानना कानून के ढांचे के भीतर मानवीय गलतियों को पहचाना जाता है। खंडपीठ ने कहा कि जब पछतावा सच्चा हो तो न्यायालय को उदारता से काम करना चाहिए। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि श्रीनंदन की माफी स्वीकार करने से न्याय का मकसद पूरा होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने सजा रद्द कर दी और अपील मंजूर कर ली।

न्यायालय की अवमानना क्या होती है, यह भी जानना आवष्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक साक्षात्कार में बताया था कि अवमानना के लिये कार्रवाई करने का संवैधानिक न्यायालयों का अधिकार न्यायालयों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है, न कि न्यायाधीशों को आलोचना से बचाने के लिए। संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 129 और 215 के माध्यम से अवमानना को दंडित करने का अधिकार देता है। इसमें न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में अवमानना तथा उसकी प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। न्यायालय की अवमानना एक विधिक अवधारणा है जो न्यायिक प्रणाली की गरिमा और अधिकार की रक्षा करती है। भारत में, न्यायालय को वर्ष 1971 के अधिनियम के तहत संबोधित किया जाता है, जो अवमानना पूर्ण कार्यों के लिये दंड को परिभाषित और निर्धारित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका के अधिकार का सम्मान और बरकरार रखा जाए। यद्यपि, अवमानना विधि की व्याख्या और अनुप्रयोग अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता पैदा करते हैं, जिससे एक नाजुक संतुलन बना रहता है जिसे बनाए रखना चाहिए।

भारत में न्यायालय अवमान को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे दिवानी अवमान और आपराधिक अवमान के रूप में हम विभाषित कर सकते हैं। वर्ष 1971 के अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत, सिविल अवमान का तात्पर्य न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेशिका या अन्य प्रक्रियाओं के प्रति जानबूझकर अवज्ञा करना है, जबकि आपराधिक अवमान में ऐसे कार्य शामिल हैं जो कलंकित करते हैं या कलंकित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसी भी न्यायालय के अधिकार को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसी भी न्यायालय के अधिकार को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वर्ष 1971 के अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत 'आपराधिक अवमान' का अर्थ है किसी भी ऐसे बात का (चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा) का प्रकाशन या कोई अन्य कार्य करने से अभिप्रेत है। इसमें किसी न्यायालय को कलंकित करना या जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की है।

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में अवमानना से बचाव भी बताए गए हैं। अधिनियम की धारा 3 के तहत यदि प्रकाशन करने वाले व्यक्तियों के पास इसके प्रकाशन के समय यह मानने का कोई उचित आधार नहीं था कि कार्यवाही लंबित थी, तो प्रकाशन को निर्दोष के रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही या उसके किसी भी चरण की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा। साथ ही धारा 5 के तहत यह भारतीय नागरिक का विशेषाधिकार प्राप्त अधिकार है कि वह जिसे सत्य मानता है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी के खिलाफ शिकायत धारा 6 के तहत कोई व्यक्ति किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकार के संबंध में सद्भावना से दिए किसी भी बयान के संबंध में न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा। अधिनियम की धारा 13 न्यायालय को किसी भी अवमान कार्यवाही में वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति देने में सक्षम बनाती है यदि यह सार्वजनिक हित या सद्भावना है। साथ ही धारा 12 (1) के प्रावधान में कहा गया है कि न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार माफी मांगने पर आरोपी को बरी किया जा सकता है या दी गई सजा माफ की जा सकती है।

न्यायालय अवमानना का वर्तमान परिदृश्य भी देखा जाना चाहिए। अप्रैल 2018 में, विधि आयोग की एक रिपोर्ट से पता चला कि उच्च न्यायालयों में 568 आपराधिक अवमान मामले और 96,310 सिविल मामले लंबित थे। इसके अलावा 10 अप्रैल, 2018 को, उच्चतम न्यायालय में 683 सिविल अवमान मामले और 15 आपराधिक अवमान मामले समाधान की प्रतीक्षा में थे। यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1971 के अधिनियम में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। यदि आवष्यक हो, तो वर्षों से उठाई गई अस्पष्टताओं और चिंताओं को दूर करने के लिये सुधार किया जाना चाहिये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये न्यायपालिका की प्रतिबद्धता, आने वाले वर्षों में न्यायालय के अधिकार की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी।

दृष्टिकोण

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

संवाद की संस्कृति और हमारी चुप्पियां

हाल के वर्षों में हुए कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययनों ने इस चिंता को वैज्ञानिक रूप से भी रेखांकित किया है। येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2025 में बताया कि मानव मस्तिष्क में 'सुनने' की प्रक्रिया केवल ध्वनि ग्रहण करने की क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें जटिल मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं ध्यान, सहानुभूति, और अर्थ-निर्माण। यह दर्शाता है कि जब हमारा ध्यान बँटा हुआ हो या मन थका हुआ हो, तो हम भले ही आवाज़ सुन लें, अर्थ नहीं पकड़ पाते है। वहीं एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि सक्रिय सुनने का अभ्यास यानी जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से सामने वाले के भावों, शब्दों और मौन को ग्रहण करता है, संवाद की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह 'सुनने की क्षमता' कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली दक्षता है। यानी अगर हम चाहें, तो सुनने का कौशल दोबारा सीख सकते हैं।

हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे चारों ओर आवाज़ें बहुत हैं, मगर सुनने वाले बहुत कम लोग है। ये शोर हर जगह है - परिवारों में, दफ़्तरों में, सड़कों पर, सोशल मीडिया आदि। हम लगातार कुछ न कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन आपाधापी में किसी और की बात सच में सुनने का धैर्य खो चुके होते हैं। याने हम सबके पास समय का अभाव है।

हाल के वर्षों में हुए कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययनों ने इस चिंता को वैज्ञानिक रूप से भी रेखांकित किया है। येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2025 में बताया कि मानव मस्तिष्क में 'सुनने' की प्रक्रिया केवल ध्वनि ग्रहण करने की क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें जटिल मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं ध्यान, सहानुभूति, और अर्थ-निर्माण। यह दर्शाता है कि जब हमारा ध्यान बँटा हुआ हो या मन थका हुआ हो, तो हम भले ही आवाज़ सुन लें, अर्थ नहीं पकड़ पाते है।

वहीं एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि सक्रिय सुनने का अभ्यास यानी जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से सामने वाले के भावों, शब्दों और मौन को ग्रहण करता है, संवाद की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह 'सुनने की क्षमता' कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली दक्षता है। यानी अगर हम चाहें, तो सुनने का कौशल दोबारा सीख सकते हैं।

आपने शायद गौर किया होगा जब कोई बच्चा गुस्से में खिलौना फेंक देता है, कोई दोस्त अचानक चुप हो जाता है, या कोई सहकर्मी मीटिंग में बेरुखा बैठा रहता है तो हम अक्सर जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं- 'वह गुस्सैल है', 'वह अभिमानी है', या 'उससे बात करना ही बेकार है।' लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर यह सोचा कि उसके भीतर उस क्षण क्या चल रहा था? शायद उसने अपनी बात कई बार कहने की कोशिश की होगी, पर कोई सच में सुनने वाला नहीं था।

'सुनना' न केवल कानों का काम नहीं, दिल का भी है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो हम उसके लिए भीतर जगह बनाते हैं उसकी तकलीफ़, उलझन या अनुभव के लिए। यही जगह आगे चलकर भरोसे में बदलती है। एक हालिया अध्ययन में यह भी पाया गया कि जब लोगों को 'गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुना' जाता है, तो न केवल बोलने वाला बल्कि श्रोता भी भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करता है। यानी सुनना सिर्फ़ सामने वाले के लिए नहीं, अपने भीतर शांति पैदा करने की क्रिया भी है।

घर में जब बच्चे की बात सुनी जाती है, तो वह खुलकर अपनी राय रखता है। दफ़्तर में किसी सहयोगी की राय को ध्यान से सुना जाए, तो वह अपने काम के प्रति ज़िम्मेदारी महसूस करता है। रिश्तों में भी यही सच है जहाँ सुनने की जगह है, वहाँ शिकायतें कम और अपनापन ज़्यादा होता है।

अपने समाज में संवाद अक्सर 'बोलने' के इर्द-गिर्द घूमता है। वक्ता की काबिलियत को सराहा जाता है, श्रोता की सजगता को नहीं। पर असल में समाज में समझ और परिवर्तन की शुरुआत सुनने से होती है। 2024 के एक शोध में यह पाया गया कि 'सुनने का अभिनय'जैसे सिर हिलाना, बीच में हाँ-हाँ करना संवाद को ऊपर-ऊपर जोड़ता है, लेकिन भीतर से अलगाव बढ़ाता है। असली सुनना तब होता है जब हम बिना निर्णय के, पूरे ध्यान से, सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं।

हम ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहाँ गलती को शर्म या दंड से जोड़ा जाता है। बच्चा कुछ गिरा दे, कर्मचारी कोई भूल कर दे, तो तुरंत ताना तय है। लेकिन अगर उस गलती को समझने का अवसर माना जाए, तो वही क्षण सीखने का बन सकता है। सुनना उस सीख की पहली सीढ़ी है जहाँ हम निर्णय नहीं, समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति देर से पहुँचा, और हमने झुँझलाकर कहा 'तुम हमेशा ऐसे ही करते हो!' जबकि वह कह सकता था 'आज रास्ते में किसी को मदद करनी पड़ी।' हमारी अधीरता ने उस संवाद का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनना दरअसल हर बार दूसरा दरवाज़ा खोलने जैसा है जहाँ दोष नहीं, समझ प्रवेश करती है।

लेकिन सुनना आसान तब होता है जब सामने वाला वैसा हो जैसा हम सोचते हैं। कठिन तब होता है, जब उसकी भाषा, पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति हमसे अलग हो। 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि लोग अक्सर 'पूर्वाग्रह के चश्मे' लगाकर सुनते हैं जिससे वे सिर्फ़ वही शब्द ग्रहण करते हैं जो उनकी राय से मेल खाते हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक बहसें या ऑनलाइन चर्चाएँ आज अक्सर 'संवाद' नहीं बल्कि 'मुक़ाबला' बन जाती हैं।

शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा हैं। वे सामने वाले के भीतर उम्मीद जगा सकते हैं या उसे भीतर तक तोड़ सकते हैं। इसलिए सुनना और बोलना दोनों में समान ज़िम्मेदारी है कि हमारे शब्द और हमारा ध्यान किसी की गरिमा को आहत न करें, बल्कि उसमें आत्मविश्वास का बीज डालें।

हमारे समय की ज़रूरत है एक ऐसा समाज जो सुनने के अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाए। घर में बच्चे की राय, स्कूल में छात्र का सवाल, दफ़्तर में सहयोगी की शंका, या किसी मज़दूर की शिकायत ये सब सिर्फ़ 'बातें' नहीं हैं, ये सामाजिक समझ की परीक्षा हैं।

सुनना कोई दुर्लभ कला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कार है। जब हम एक-दूसरे को सुनते हैं, तो हम मतभेदों के बावजूद साथ रहने की कला सीखते हैं। यही वह तैयारी है जो समाज को हिंसा, नफ़रत और असहिष्णुता से बचाती है।

शोध बताते हैं कि सुनने की क्षमता अभ्यास से निखर सकती है, लेकिन उसका पहला कदम हमेशा भीतर से शुरू होता है ठहरने और ध्यान देने से। अगर हम एक-दूसरे को थोड़ा और ध्यान से सुन सकें, अपने घरों में, अपने विद्यालयों में, अपने समाज में, तो शायद हम उस दुनिया के थोड़ा क़रीब पहुँचेंगे जहाँ समझ और सहानुभूति की जगह है। क्योंकि अंततः, समझने की शुरुआत हमेशा एक साधारण क्रिया से होती है सुनने से।

ब्रह्मांड

ब्रजेश कानूनगो

लेखक साहित्यकार और ब्लॉगर हैं।

अद्भुत और दिलचस्प प्रक्रिया है ग्रहों का निर्माण

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने अंतरिक्ष में बन रहे नए तारे के निर्माण की एक अद्भुत तस्वीर ली है। यह तस्वीर पृथ्वी से लगभग 625 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे के निर्माण को दर्शाती है, जो हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) के सबसे नजदीकी तारा-निर्माण क्षेत्रों में से एक में अवस्थित है। इससे पहले भी इसी माध्यम से नासा ने कई महत्वपूर्ण तस्वीरों को जारी किया था। पिलर्स ऑफ क्रिएशन नामक तस्वीर ईगल नेबुला के अंदर धूल और गैस के विशालकाय स्तंभों को दर्शाती है, जहां नए तारे बन रहे हैं। JWST ने SMACS 0723 नाम के एक आकाशगंगा समूह की तस्वीर ली है, जो लगभग 13 अरब साल पुरानी है ।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) नासा का प्रमुख खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी मिशन है, जिसे 25 दिसंबर, 2021 को प्रक्षेपित किया गया और इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 (L2) पर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने अंतरिक्ष में बन रहे नए तारे के निर्माण की एक अद्भुत तस्वीर ली है। यह तस्वीर पृथ्वी से लगभग 625 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे के निर्माण को दर्शाती है, जो हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) के सबसे नजदीकी तारा-निर्माण क्षेत्रों में से एक में अवस्थित है।

इससे पहले भी इसी माध्यम से नासा ने कई महत्वपूर्ण तस्वीरों को जारी किया था। पिलर्स ऑफ क्रिएशन नामक तस्वीर ईगल नेबुला के अंदर धूल और गैस के विशालकाय स्तंभों को दर्शाती है, जहां नए तारे बन रहे हैं। JWST ने SMACS 0723 नाम के एक आकाशगंगा समूह की तस्वीर ली है, जो लगभग 13 अरब साल पुरानी है । सदर्न रिंग (Southern Ring) तस्वीर एक नेबुला के एक अन्य तारे को दर्शाती है, जो धूल और गैस से बना है। स्टीफंस क्विनटेट (StephenÓs Quintet) तस्वीर पांच आकाशगंगाओं के एक समूह को दर्शाती है, जो एक दूसरे के करीब स्थित हैं। कैरिना नेबुला (Carina Nebula) तस्वीर ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेबुला में से एक को दर्शाती है, जो पृथ्वी से 7,600 प्रकाश वर्ष दूर है। इसी तरह JWST ने बृहस्पति ग्रह की तस्वीर ली है, जिसमें उसके तीन चंद्रमा यूरोपा, थेबे और मीटिस को देखा जा सकता है। WASP-96b तस्वीर एक ग्रह के वातावरण में मौजूद तरंगों को दर्शाती है, जो पृथ्वी से 1,150 प्रकाश वर्ष दूर है । इन तस्वीरों को भी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया।

नए तारे के निर्माण की हाल ही में जारी ताजा तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एडवांस्ड इन्फ्रारेड क्षमता का उपयोग करके ली गई है, जो धूल और गैस के बादलों के भीतर झांकने में सक्षम है। तस्वीर में एक तारे से गैस और धूल का गुबार निकलता हुआ दिखाया गया है, जो नए तारे के निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया को दर्शाता है ।

आकाश में तारा बनने की प्रक्रिया एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल हैं। यह प्रक्रिया लगभग 13.6 अरब वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था।

तारा बनने की प्रक्रिया एक गैसीय क्लाउड (नेबुला) से शुरू होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। जब गैसीय क्लाउड में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ता है, तो यह संकुचित होने लगता है और एक प्रारंभिक तारा बन जाता है। जब तारा का तापमान और दबाव बढ़ता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदल जाते हैं और ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका विकास कई चरणों में होता है, जिसमें यह लाल विशालकाय, श्वेत बौना, और अंततः एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल जाता है। शोध निष्कर्षों के अनुसार प्रारंभिक तारा बनने की प्रक्रिया लगभग 13.6 अरब वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। पहले तारे लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले बने थे, जो विशाल और गर्म थे। समय के साथ, तारों की विविधता बढ़ी, जिसमें छोटे और ठंडे तारे भी शामिल थे। तारों के समूहों ने आकाशगंगाओं का निर्माण किया, जो आज हम देखते हैं।

हमारी पृथ्वी भी एक तारा है। पृथ्वी के जीवन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी बहुत रोचक होगा। पृथ्वी का जीवन काल लगभग 4.54 अरब वर्ष है, जो ब्रह्मांड के जीवन काल का लगभग एक तिहाई है। आइए जानते हैं कि पृथ्वी के जीवन काल के बारे में क्या उपलब्ध जानकारी है।

पृथ्वी के जीवन काल को कई ईऑन याने वृहद कालखंडों और चरणों में समझा गया है। तारा निर्माण की विविध प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हेडियन ईऑन (4.54 - 4 अरब वर्ष पूर्व) में हमारी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, यह तब एक गर्म और तरल अवस्था में थी। आर्कियन ईऑन (4 - 2.5 अरब वर्ष पूर्व) में पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और अनेक महासागरों का निर्माण हुआ। प्रोटेरोज़ोइक ईऑन (2.5 अरब - 541 मिलियन वर्ष पूर्व) में पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ और यह धीरे धीरे विकसित होने लगा। इसके पश्चात फेनज़ोइक ईऑन (541 मिलियन वर्ष पूर्व - वर्तमान) से पृथ्वी पर जीवन विविधता पूर्ण और जटिल होता गया और आज का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ।

करोड़ों वर्ष पुराने इस अनूठे सितारे पर प्रकृति और प्राणियों के अद्भुत सौंदर्य को निहारना और अनुभव करना कितना सुखद व आनंददायी है यह कौन घुम्मकड़ भला नकारना चाहेगा। करोड़ों पर्यटक और ट्रैवलर इसी रोमांच की तलाश में दुनिया का कोना कोना छान आते हैं। इनके ट्रैवलॉग और यूट्यूब वीडियो को घर बैठे देखना हमारे लिए भी कम सुखद नहीं है।

राष्ट्रीय गणित दिवस पर विशेष

विकसित भारत के निर्माण में गणित का योगदान

डॉ. ताड़केश्वर नाथ मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर (गणित) संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, भोपाल

हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय गणित दिवस हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम गणित के महत्व को केवल एक अकादमिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की बुनियादी शक्ति के रूप में समझें। यह दिवस महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जीवन और कार्य इस सत्य का सशक्त प्रमाण है कि गणितीय प्रतिभा सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्र और मानवता को नई दिशा दे सकती है। विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना में गणित की भूमिका केन्द्रीय है, क्योंकि आधुनिक विकास तर्क, विश्लेषण और वैज्ञानिक सोच पर आधारित होता है।

भारतीय सभ्यता में गणित की परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है। शून्य की अवधारणा, दशमलव स्थान-मूल्य पद्धति, ज्यामिति और बीजगणित में भारतीय विद्वानों का योगदान आज भी वैश्विक विज्ञान की आधारशिला है। यह विरासत हमें यह बोध कराती है कि गणित भारत के बौद्धिक डीएनए का हिस्सा रहा है। आज जब भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब यह परंपरा आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नीति निर्माण में नए रूप में अभिव्यक्त हो रही है।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में गणित की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। बजट निर्माण, कर संरचना, वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग प्रणाली और शेयर बाजार-सभी गणितीय मॉडल और सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास दर का आकलन आँकड़ों, पूर्वानुमानों और संभाव्यता के माध्यम से ही किया जाता है। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब आर्थिक नीतियाँ भावनाओं के बजाय तथ्यों और गणितीय तर्क पर आधारित हों। संसाधनों का संतुलित वितरण, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास-इन सभी में गणित एक मौन मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

तकनीकी प्रगति में गणित का योगदान और भी व्यापक रूप में सामने आता है। आज का युग डिजिटल और तकनीक-संचालित है, जहाँ कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों की नींव गणित पर ही टिकी हुई है। एल्गोरिद्म, कोडिंग, एन्क्रिप्शन और नेटवर्क डिज़ाइन-सभी गणितीय तर्क में निहित हैं। भारत की डिजिटल पहलें, जैसे डिजिटल भुगतान प्रणाली, ई-गवर्नेंस और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गणितीय सटीकता और दक्षता के बिना संभव नहीं होतीं। विकसित भारत की परिकल्पना में तकनीक-सक्षम शासन एक प्रमुख स्तंभ है, और इसके मूल में गणित ही है।

अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ भी गणितीय सामर्थ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उपग्रहों की कक्षीय गणनाएँ, प्रक्षेपण तकनीक, मिसाइल प्रणाली और रडार नेटवर्क-इन सभी में उच्च स्तरीय गणितीय मॉडलिंग का उपयोग होता है। भारत के चंद्रयान और मंगल मिशन यह दर्शाते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद सटीक गणितीय योजना कैसे असाधारण सफलता दिला सकती है। आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत के निर्माण में गणित की भूमिका इसलिए भी अनिवार्य है।

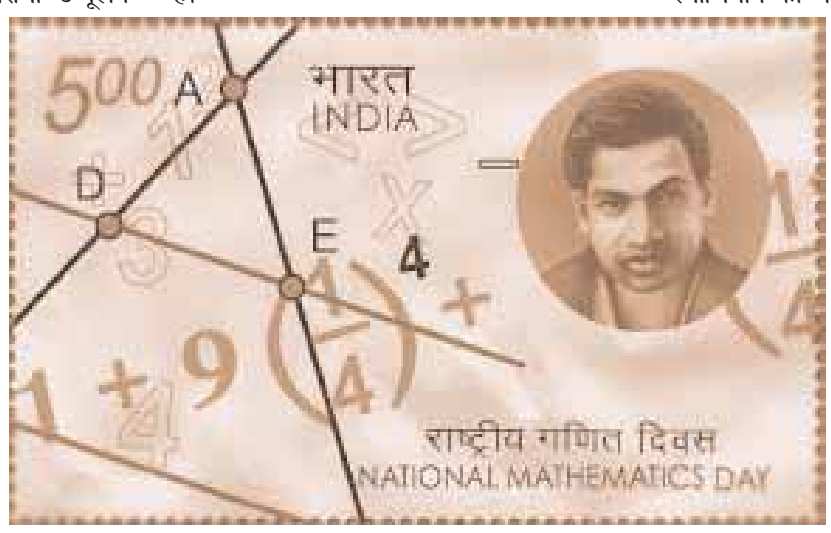

राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन के योगदान को स्मरण करने का अवसर भी है, जिनकी गणितीय चेतना आज के भारत के लिए विशेष प्रेरणा है। रामानुजन ने संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियों और गणितीय विश्लेषण में ऐसे मौलिक सूत्र दिए, जिनका उपयोग आज भी आधुनिक गणित और भौतिकी में किया जाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि मौलिक सोच और रचनात्मकता किसी औपचारिक व्यवस्था की मोहताज नहीं होती। विकसित भारत के लिए यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवाचार और अनुसंधान तभी पनपते हैं जब स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिले। रामानुजन का योगदान केवल गणितीय खोजों तक सीमित नहीं है; वह आत्मविश्वास और सांस्कृतिक स्वाभिमान का भी प्रतीक है। औपनिवेशिक काल में उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय प्रतिभा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। आज जब भारत वैश्विक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है, तब रामानुजन की विरासत युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि सीमाएँ परिस्थितियों की नहीं, बल्कि सोच की होती हैं। विकसित भारत के निर्माण में यह मानसिकता अत्यंत आवश्यक है।

सामाजिक विकास में भी गणित की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। जनसंख्या अध्ययन, स्वास्थ्य योजनाएँ, महामारी प्रबंधन, शिक्षा नीति और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम-इन सभी की सफलता सटीक आँकड़ों और सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करती है। समावेशी और न्यायपूर्ण विकास तभी संभव है जब नीतियाँ वास्तविक आंकड़ों और वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित हों। गणित इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जो किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। शिक्षा के क्षेत्र में गणित विकसित भारत की नींव है। गणित केवल अंकगणित नहीं, बल्कि तार्किक सोच, समस्या-समाधान और निर्णय क्षमता को विकसित करने का माध्यम है। रामानुजन का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि जिज्ञासा और रचनात्मकता का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर यह आवश्यक है कि गणित शिक्षा को भयमुक्त और प्रेरणादायक बनाया जाए, ताकि छात्र इसे बोझ नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखें।

उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में भी गणित का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप संस्कृति, उद्योग 4.0, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाजार विश्लेषण-सभी मात्रात्मक तर्क और अनुकूलन पर निर्भर करते हैं। जब युवा गणितीय सोच के साथ उद्यमिता को अपनाते हैं, तो वे रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया विकसित भारत की आर्थिक मजबूती का आधार बनती है।

22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाना हमें यह याद दिलाता है कि गणित केवल विशेषज्ञों का विषय नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की साझा संपदा है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गणित को शिक्षा, नीति, तकनीक और नवाचार के केंद्र में रखा जाए। रामानुजन की विरासत और गणितीय परंपरा हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हम तर्क, सटीकता और रचनात्मकता को अपनाएँ, तो भारत न केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से विकसित होगा, बल्कि बौद्धिक और मानवीय दृष्टि से भी एक आदर्श राष्ट्र बन सकेगा।

मजदूर भाइयों, अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी है : शिवराज

भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विकसित भारत जी राम जी बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब ये कानून का रूप ले चुका है। इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी एक्ट के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि इसके बारे में भ्रम फैलाने की साजिश हो रही है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि विकसित भारतः जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मजदूर भाइयों, अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी है। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए इसी साल रू. 1,51,282 करोड़ से अधिक की विशाल धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव और गरीबी मुक्त - रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के काम हाथ में लिए जाएंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ कृषि कार्य के समय छोटे-छोटे किसान भाई-बहनों को दिक्कत न हो, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। यह कानून गरीब के हक में है, विकास के हक में है और यह कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। यह विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है।

उन्होंने इसके बारे में आगे बताया कि इसमें एक और विशेष प्रावधान किया गया है, प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर प्रस्तावित राशि रू. 1,51,282 करोड़ में 9 प्रतिशत निकाल लें तो लगभग रू. 13,000 करोड़ होता है, इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी - पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित टेक्निकल स्टाफ को समय पर पर्याप्त वेतन मिलेगा, ताकि वे पूरी क्षमता से कार्य करा सकें।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने लोगों से सच को जनता तक पहुंचाने की अपील की।

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय धार के विद्यार्थियों ने इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय और केंद्रीय संग्रहालय का भ्रमण किया

धार। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय धार के कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय और केंद्रीय संग्रहालय का भ्रमण किया। प्राचार्य नीरज अस्थाना एवं प्रधान अध्यापिका दीपशिखा कुमावत के मार्गदर्शन में 20 दिसम्बर को प्रातः 7 बजे विद्यार्थी उत्साह के साथ बस में रवाना हुए और चिड़ियाघर पहुँचने पर कर्मचारियों से सुरक्षा नियमों व जानवरों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। छात्रों ने शेर, हाथी,सफेद बाघ, तेंदुआ, स्नेक पार्क, काला हिरण, हाथी, दरियाई घोड़ा, विभिन्न पक्षियों और सरीसृपों जैसी अनेक प्रजातियों को नज़दीक से देखा तथा उनके रहने के तरीके, आदतों और संरक्षण के महत्व को समझा। पूरे भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अनुशासन व सक्रिय सहभागिता दिखाई। अनुरक्षक शिक्षक / शिक्षिका के रूप में जितेंद्र वैष्णव, राहुल पाण्डे, अंजली यादव, कविता शामिल हुए। लौटते समय छात्रों में नई जानकारियाँ सीखने का उत्साह और खुशी साफ झलक रही थी। यह भ्रमण उनके लिए अत्यंत उपयोगी, शिक्षाप्रद और यादगार अनुभव साबित हुआ।

विधायक हेमंत खंडेलवाल बोले

मैं और कांग्रेस के साथी तो हैं मजबूत, करा लेंगे इलाज, पर मेडिकल कॉलेज जनता के लिए बेहद जरूरी

एस. द्विवेदी बैतूल। शहर के कोसमी क्षेत्र में पीपीपी मोड के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। कल यानि 23 दिसम्बर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगतप्रकाश नड्डा व मुख्यमंत्री डॉ. यादव, बैतूल विधायक व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ इसका भूमि पूजन करेंगे। रविवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक ने इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण की रूपरेखा की जानकारी दी। इसके अलावा पत्रकारों की जिज्ञासा व सवालों के जवाब भी दिए। इसी चर्चा के दौरान वे कह उठे कि मैं और कांग्रेस के साथी तो मजबूत है, वे इलाज करा ही लेंगे, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज जनता के लिए है। इससे कमजोर वर्ग को बेहतर इलाज अपने क्षेत्र में ही मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेज हमारे जिले के स्वास्थ्य ढांचे को बदलने वाला ऐतिहासिक कदम होगा। बैतूल जिला आज भी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में जिला अस्पताल में 300 बिस्तरों की क्षमता है। गंभीर बीमारियों की उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। जिले से 100 किमी के दायरे में कोई उच्च स्तरीय अस्पताल नहीं है। गंभीर रोगियों को उपचार हेतु नागपुर या भोपाल जाना पड़ता है, इससे लोगों का अनावश्यक समय व धन खर्च होता है। इस स्थिति में जिले में मेडिकल कॉलेज बेहद जरूरी था। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल के अंतर्गत सरकार द्वारा निजी भागीदार के रुप में स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन को चुना गया है, जो प्रतिष्ठित आरकेडीएफ ग्रुप का हिस्सा है। इसके द्वारा देश में 6 विश्वविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अतः चिकित्सा शिक्षा एवं अस्पताल प्रबंधन में इसका महत्वपूर्ण अनुभव है।

25 एकड़ में 230 करोड़ से कोसमी में बनेगा मेडिकल कॉलेज- इस मेडिकल कॉलेज परिसर के विकास हेतु सरकार द्वारा कोसमी क्षेत्र की 25 एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर दी जा रही है। कॉलेज के निर्माण, अवसंरचना और उपकरणों की स्थापना पर लगभग 230 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। यह निवेश जिले में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। आने वाले तीन सालों के भीतर कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल के रूप में उपयोग किया जाएगा, एनएमसीआई के मानकों के अनुसार 150 एमबीबीएस सीटो हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और बिस्तरों की संख्या 300 से बढ़ाकर 605 एवं नई आईसीयू, इमरजेंसी और स्पेशियल्टी यूनिट्स स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के मन में किसी तरह का भ्रम न रहे, इसीलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वर्तमान की तरह 75 प्रतिशत बिस्तरों के मरीजो का उपचार पूर्णतः निशुल्क रहेगा, बचे हुए 25 प्रतिशत बिस्तरो के मरीजों हेतु सीमित शुल्क लिया जाएगा। मध्यम वर्ग एवं गैर आयकर दाताओं को कनशेशनल रेट मिलेगें। आयकरदाता भी सीजीएचएस पैकेज रेट के हिसाब से किफ यती इलाज करावा सकेगें। अर्थात गरीब एवं पात्र लोगों का निःशुल्क उपचार जारी रहेगा तथा अब उन्हें जिले में ही उन्नत सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ जिले में ही उपलब्ध हो।

पत्रकारों से चर्चा करते आमला विधायक व एमडी डाक्टर योगेश पंडाग्रे ने बताया कि रोजगार के नजरिये से भी मेडिकल कालेज जिले में मील का पत्थर साबित होगा। जिले के विद्यार्थियों को एमबीबीएस तथा अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रम पढ़ने हेतु अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की तैयारियों का विधायक खंडेलवाल ने लिया जायजा

23 दिसंबर को पुलिस ग्राउंड, बैतूल में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अधिकारियों के साथ स्थल पर पहुँचकर जायजा लिया। कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा के मुख्य आतिथ्य तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित होगा। निरीक्षण के दौरान श्री खंडेलवाल ने संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक मिथलेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा,अतिथियों के आगमन, मंच व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात तथा अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की।

बैतूल पुलिस के 700 से अधिक जवानों ने लिया हार्टफुलनेस ध्यान का आनंद

तनाव मुक्त कार्यप्रणाली की ओर बढ़ाए कदम

बैतूल। पुलिस विभाग की चुनौतीपूर्ण कार्यशैली के बीच मानसिक शांति और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से बैतूल जिले के सभी थानों में विशेष हार्टफुलनेस ध्यान सत्रों का सफल आयोजन किया गया। हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक दाजी कमलेश डी. पटेल की प्रेरणा और मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना के मार्गदर्शन में आयोजित सत्रों में जिले के 700 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अधिकारियों का रहा विशेष नेतृत्व – बैतूल पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती जोशी मैम के कुशल निर्देशन में इन सत्रों को जिला स्तर पर क्रियान्वित किया गया। इस अभियान में जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे जिले के प्रत्येक थाने तक ध्यान की लहर पहुची।

हार्टफुलनेस प्रशिक्षकों द्वारा संचालित इन सत्रों में पुलिसकर्मियों को हृदय आधारित ध्यान की सरल तकनीकों का अभ्यास कराया गया। सत्रों के दौरान उपस्थित पुलिस बल ने मानसिक शांति का अनुभव किया। कार्य के दौरान आने वाले तनाव को प्रबंधित करने के तरीके भी सीखे।

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि पुलिस बल की मानसिक सुदृढ़ता विभाग की प्राथमिकता है। ध्यान के इन सत्रों से जवानों के व्यवहार और कार्यक्षमता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सभी प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना की और इसे नियमित रूप से जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

एसजीएसआईटीएस संस्थान में फार्मेसी एलुमनी मीट का आयोजन

इंदौर/देवास। आज एसजीएसआईटीएस परिसर में फार्मेसी एलुमनी मीट (सिल्वर जुबली बैच-2000) का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसजीएसआईटीएस के निदेशक श्री नितेश पुरोहित जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसजीएसआईटीएस फार्मेसी विभाग के पूर्व छात्रों (एलुमनी) ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर पूर्व छात्र-छात्राओं के साथ-साथ वर्तमान छात्र भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस एलुमनी मीट में ऐसे विशिष्ट एलुमनी शामिल हुए, जो वर्तमान में अनुसंधान, शिक्षा, उद्योग एवं अन्य विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और जो संस्थान के लिए गौरव का विषय हैं। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें आरजीपीवी के पूर्व कुलपति डॉ. पियूष त्रिवेदी, एसजीएसआईटीएस के डीन फैकल्टी डॉ. ललित पुरोहित, गवर्निंग बॉडी के सदस्य श्री मनीष गुप्ता शामिल थे। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत फार्मेसी एलुमनी–श्री गिरीश परगांवकर, श्री संजय तिवारी, डॉ. कपिल जोशी, डॉ. पंकज खापरा– अनिल भाटिया, तथा एमपी फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष श्री संजय जैन एवं अन्य एलुमनी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

फार्मेसी एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रभाष जाटव ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों एवं एलुमनी सदस्यों का अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि श्री नितेश पुरोहित जी ने अपने संबोधन में फार्मेसी एलुमनी एसोसिएशन एवं उसके सभी सदस्यों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी तथा भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर सफलतापूर्वक आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने फार्मेसी एलुमनी को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में फार्मेसी विभाग से डॉ. विनीत सिंह, प्रो. मीना तिवारी सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार साझा करते हुए फार्मेसी प्रोफेशन को सशक्त बनाने, समाज एवं राष्ट्र निर्माण में फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली अलूमनी ने गीत और मिमिक्री कर समा बांध दिया जिनमें मुख्य तौर पर अशोक देवांगन मुंबई से, प्रीत स्वरूप भोपाल से, डॉ. प्रकाश सोनी, डॉ. आरसी माहेश्वरी, अर्चना सेंगवा डॉ. शुधा सिंह रहीं ! कार्यक्रम के अंत में फार्मेसी एलुमनी एसोसिएशन के सचिव श्री अजय दासों दी द्वारा धन्यवाद प्रस्तुत किया गया।

त्रिमूर्ति नगर में हिंदू सम्मेलन हेतु कार्यालय का भव्य उद्घाटन

हिंदू संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 4 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले विशाल 'हिंदू सम्मेलन' की तैयारियाँ प्रारंभ

धार। हिंदू संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 4 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले विशाल 'हिंदू सम्मेलन' की तैयारियाँ जोर-शोर से प्रारंभ हो गई हैं। इसी क्रम में त्रिमूर्ति नगर बस्ती के लिए निर्धारित कार्यालय का विधि-विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ।

संत श्री सुरेशानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ शुभारंभ- त्रिमूर्ति नगर स्थित मकान नंबर 129 (सोलंकी जी के निवास) पर आयोजित इस गरिमामयी समारोह में पूज्य संत श्री सुरेशानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री के कर-कमलों द्वारा कार्यालय का शुभ उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा एवं श्री राम स्तुति का पाठ कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

सम्मेलन की रूपरेखा एवं रणनीतियां- कार्यालय उद्घाटन के पश्चात आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से

पीले चावल का निमंत्रण- सम्मेलन के लिए प्रत्येक घर जाकर पीले चावल देकर जन-जन को आमंत्रित करने की योजना बनाई गई।

भूमि पूजन- 4 जनवरी के मुख्य आयोजन हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।

स्थल चयन – कार्यक्रम परिसर में मंच, भजन मंडली स्थल एवं वर्किंग एरिया (कार्य स्थल) के चयन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यकारिणी गठित-हिंदू सम्मेलन को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु सर्वानुमति से पदाधिकारियों की घोषणा की गई।

संयोजक अशोक जैन, सह-संयोजक संतोष बाबूलाल पांडेय, गुंजन जोशी, सोहन यादव

कोषाध्यक्ष अशोक मनोहर जोशी, रितेश शर्मा, दशरथ सिग्गा को चुना गया।

संयोजक अशोक जैन एवं सह-संयोजक संतोष बाबूलाल पांडे ने संबोधन में सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर त्रिमूर्ति नगर, भोज नगर एवं मगजपुरा के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। कार्यालय उद्घाटन में विशेष रूप से बस्ती के हुकुम लश्करी, संजय शर्मा, प्रफुल्ल जोशी नंदन जोशी ,सुनील रघुवंशी अधिवक्ता, सूरज मुकाती,कपिल चौधरी, ओम सोलंकी मातृ शक्तियों में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मीना दुबे, महिमा गुप्ता, इति वैष्णव विशेष रूप से उपस्थित रही।

कार्यक्रम की जानकारी कार्यक्रम प्रमुख जगदीश चंद्र जोशी द्वारा प्रदान की गई।

संक्षिप्त समाचार

इटारसी-भोपाल होकर चलेगी हैदराबाद-अजमेर स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने लिया फैसला

नर्मदापुरम/इटारसीपश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए हैदराबाद-अजमेर-हैदराबाद के बीच एक-एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशनों से होकर गुजरेगी।रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 07731 हैदराबाद-अजमेर स्पेशल 23 दिसंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन तीसरे दिन मध्यरात्रि 2:15 बजे अजमेर पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 07732 अजमेर-हैदराबाद स्पेशल 27 दिसंबर 2025 को शाम 6:50 बजे अजमेर से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 11:00 बजे हैदराबाद पहुंचेगी।कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी स्पेशल ट्रेनयह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, मेडचल, कमारेड्डी, निजामाबाद जंक्शन, बसर, धर्माबाद, मुदखेड, नांदेड़, पूर्णा जंक्शन, बासमत, हिंगोली डेक्कन, वाशिम, अकोला जंक्शन, खंडवा जंक्शन, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, रतलाम जंक्शन, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़ जंक्शन, भीलवाड़ा, बिजयनगर और नसीराबाद शामिल हैं।यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास के कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस स्पेशल ट्रेन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन, रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें।

तवा नदी पर रेत निकालने बनाया स्थाई रास्ते को तोड़ा

रेत कंपनी पर कार्रवाई के खनिज निगम को भेजा प्रस्ताव

नर्मदापुरम नर्मदापुरम में ग्राम मेहरा घाट के पास तवा नदी पर रेत निकालने बनाएं अस्थाई रास्ते को तोड़ दिया गया। राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने शुक्रवार शाम 5.30 बजे जेसीबी से उक्त रास्ते को तोड़ा। साथ ही रेत ठेकेदार एमडीओ मेंसर्स वेलोसिटी माइनिंग वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव खनिज निगम को भेजा है।कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देश पर जिले में रेत के अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण के विरुध खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण जिले में कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार ग्राम मेहरा घाट में तवा नदी पर रेत के उत्खनन कर परिवहन करने के लिए नदी में अस्थाई कच्चा रास्ता बनाए जाने की सूचना पर राजस्व विभाग से एसडीएम जय सोलंकी, नायब तहसीलदार रुचि गोयल, जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम, देहात थाना प्रभारी सौरभ पांडे टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच की और अस्थाई कच्चा रास्ता / ब्रिज को जेसीबी से तोड़ा।रेत परिवहन किए जाने के लिए ग्राम पंचारा कला से होकर रेत के वाहन का परिवहन किया जाता था। लेकिन लगभग दो माह पूर्व ग्राम पांजरा कला में एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से रेत ठेकेदार द्वारा ऑप्शनल मार्ग के रूप में ग्राम मेहरा घाट में शासकीय कच्चे रास्ते से होकर नदी में अस्थाई रास्ता बनाकर स्वीकृत रेत खदान से रेत का परिवहन किया जा रहा था। नदी में पानी में अवैधानिक रूप से बनाये गए अस्थाई कच्चा रास्ता /ब्रिज को जांच दल द्वारा नष्ट कर दिया गया है। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कंपनी भेजा है।

किसानों में आधुनिक कृषि यंत्रों के क्रय प्रति बढ़ा रुझान, सुपर सीडर से गेहूं की बेहतर बोनी

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में अनुदान योजनाओं के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों को सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसी क्रम में कृषक श्री रमेश सिंह कुशवाह, निवासी फारंगपुर पंचायत धामनोदा, विकासखंड विदिशा, जिला विदिशा द्वारा सुपर सीडर मशीन अनुदान पर क्रय की गई हैकृषक द्वारा इस वर्ष 25 नवंबर को सुपर सीडर मशीन से गेहूं की बोनी की गई थी। कृषक ने बताया कि कि बोई गई फसल का अंकुरण अत्यंत अच्छा हुआ है, जिससे वे काफी संतुष्ट हैं।इसके साथ ही आज पुनः सुपर सीडर मशीन द्वारा गेहूं की बोनी की गई। कृषक ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 100 बीघा क्षेत्र में सुपर सीडर मशीन से बोनी की जा चुकी है। सुपर सीडर मशीन के उपयोग से समय, लागत एवं श्रम की बचत के साथ-साथ फसल उत्पादन में भी सुधार देखा जा रहा है। अनुदान पर उपलब्ध आधुनिक कृषि यंत्रों से किसानों में तकनीक अपनाने का उत्साह बढ़ा है, जो टिकाऊ एवं उन्नत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रिश्वतखोरी में पकड़े गए कृषि उप संचालक हेडाऊ सस्पेंड लाइसेंस बहाल करने व्यापारी से मांगे थे एक लाख रुपए

नर्मदापुरम नर्मदापुरम में 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कृषि विभाग के उप संचालक (डिप्टी डायरेक्टर) जे.आर. हेडाऊ को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। निलंबन का आदेश कृषि मंत्रालय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अवनीश मिश्रा ने जारी किया है, जो शुक्रवार देर रात सामने आया।

आदेश में बताया गया है कि लोकायुक्त संगठन ने जे.आर. हेडाऊ को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि के दौरान जे.आर. हेडाऊ का मुख्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय, शहडोल संभाग तय किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

लाइसेंस बहाल करने के बदले मांगी थी रिश्वत

यह कार्रवाई 8 दिसंबर को की गई थी। शिकायतकर्ता राजनारायण गुप्ता, जो कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हैं, ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई की खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस तीन महीने पहले निलंबित कर दिया गया था।

लाइसेंस बहाल करने के बदले उप संचालक जे.आर. हेडाऊ ने एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद सौदा 50 हजार रुपए में तय हुआ और पहली किस्त के तौर पर 40 हजार रुपए देने पर सहमति बनी। इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई।

पैसे लेकर खुद ड्रॉज में रखे-8 दिसंबर को जब शिकायतकर्ता 40 हजार रुपए लेकर उप संचालक के कार्यालय पहुंचा, तो हेडाऊ ने पैसे खुद न लेकर टेबल की दराज में रखवा दिए। जैसे ही शिकायतकर्ता बाहर निकला, लोकायुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई कर उप संचालक को रंगेहाथ पकड़ लिया। इस मामले में लाइसेंस शाखा देखने वाले क्लर्क संजय साहू पर भी रिश्वत मांगने और सहयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। लोकायुक्त मामले की जांच कर रही है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, शहडोल संभाग शहडोल रहेगा। निलंबन अवधि में जेआर हेडाऊ को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

लाइसेंस बहाल के नाम पर मांगे थे एक लाख रुपए-कृषि विभाग से रिटायर्ड राजनारायण गुप्ता ने लोकायुक्त से उप संचालक हेडाऊ द्वारा रिश्वत में एक लाख रुपए लेने की शिकायत की थी। राजनारायण अपने भाई की खाद बीज की दुकान को देखते है। 3 महीने पहले उप संचालक जेआर हेडाऊ ने उनका लाइसेंस निलम्बित किया था। शिकायतकर्ता राजनारायण गुप्ता ने कहा लाइसेंस बहाल करने के लिए उसे 2 महीने से परेशान किया जा रहा था।

एक लाख रुपए की डिमांड की। जिसे कम करते करते 50 हजार रुपए में फाइनल हुआ। पहले 40 हजार रुपए देने पर उन्हें राजी किया। जिसकी लोकायुक्त में शिकायत की थी। 8 दिसम्बर को जब वो रुपए लेकर पहुंचा तो उप संचालक हेडाऊ ने रुपए खुद झूलने के बदले चैंबर में टेबल के अंदर ड्राज में रख दिया। रुपए रखकर जैसे ही वो बाहर पहुंचा, तत्काल लोकायुक्त टीम अंदर चैंबर में पहुंची और उप संचालक जेआर हेडाऊ को पकड़ लिया। मामले में शिकायतकर्ता राजनारायण गुप्ता ने लाइसेंस शाखा देखने वाले क्लर्क संजय साहू पर भी डिमांड करने और ध्यान रखने कहने जैसे आरोप लगाए थे।

23 दिसंबर को जारी होगी मतदाता सूची का प्रारूप:नर्मदापुरम में अनुपस्थित मिले

10,984 मतदाताओं को जाएंगे नोटिस

नर्मदापुरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के 10,984 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। ये वे मतदाता हैं, जो एसआईआर सर्वे के दौरान बीएलओ को घर पर नहीं मिले या जानकारी देने से बचते पाए गए थे।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि एसआईआर-2026 के तहत ऐसे अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस भेजकर निर्धारित समय में ईआरओ कार्यालय बुलाया जाए, ताकि वे अपने जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर समय पर नोटिस की तामीली और उसकी पुष्टि की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए ईआरओ कार्यालय में हेल्प डेस्क और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नोटिस की तामीली से लेकर दावे-आपत्तियां प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया बीएलओ और निर्वाचन अमले द्वारा की जाएगी।23 दिसंबर से 10984 मतदाताओं को जाएंगे नोटिस 23 दिसंबर से नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा, होशंगाबाद, पिपरिया और सोहागपुर विधानसभा क्षेत्रों के 10,984 अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान मतदाताओं को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा जिले में मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि की श्रेणी में आने वाले 39,335 मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।जिले में बनेंगे 96 नए मतदान केंद्रमतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद नर्मदापुरम जिले में 96 नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 1,283 हो जाएगी।

कोसमी में बाढ़ राहत आपदा खोज एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन

बैतूल (निप्र)। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बैतूल द्वारा एक दिवसीय बाढ़ राहत आपदा खोज एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन शुक्रवार को कोसमी डेम में किया गया। मॉक ड्रिल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनिता पटेल एवं अध्यक्ष डीडीएमए के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड श्री इंदल उपनारे ने बताया कि मॉक ड्रिल में बाढ़ आपदा राहत खोज एवं बचाव तकनीक , बाढ़ के दौरान इंप्रोवाइज मेथड से आपदा सामग्री का निर्माण करना एवं इस्तेमाल के तरीके बताए। साथ ही बाढ़ आपदा से संबंधित दुर्घटना, पानी में डूबने पर प्राथमिक उपचार एवं बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि यह प्रशिक्षण मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में आयोजित ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग डिजास्टर रिस्पांस टीम मध्य प्रदेश के अनुमोदित प्रस्ताव के तहत किया गया।इस अवसर पर जिला कमांडेंट होमगार्ड श्री इंदल उपनारे, श्रीमती सुनीता पन्द्रे प्लाटून कमाण्डर होमगार्ड एवं जेएल कोठारी प्लाटून कमांडर होमगार्ड हरदा, श्री बीएस कुशराम एएसआई श्री बलीराम सरयाम हवलदार अनुदेशक, श्री अवधेश वर्मा हवलदार स्टोरमेन एवं एसडीईआरएफ जवान पंकज, योगेश, भुपेन्द्र, रामकरण, दिनेश, पियूष, कैलाश, शशांक, अर्जुन, लवकेश तथा फ्लड रेस्क्यू टास्क फोर्स के सदस्य, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, जनसंपर्क विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी बैतूल, महिला बाल विकास विभाग एवं रेल्वे विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा होमगार्ड, एसडीईआरएफ एवं सिविल डिफेन्स के सदस्य सम्मिलित हुए।

केसीसी पर जागरूकता बैठक, किसानों को ऋण सुविधाओं से जोड़ने पर जोर

विदिशा (निप्र)। डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर श्रीमती श्वेता सत्या द्वारा आज विदिशा जिले के कुरवाई विकासखंड के आजीविका मिशन भवन में किसानों एवं संबंधित हितधारकों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बैंकर्स, सीएससी सेंटर प्रतिनिधि, कृषि सखी, समितियों के प्रबंधक, कृषि विस्तार अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।बैठक के दौरान श्रीमती श्वेता सत्या ने केसीसी योजना के लाभों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केसीसी के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर समय पर ऋण, खेती से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति, बीज, खाद, कीटनाशक एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता में सुविधा मिलती है। साथ ही फसल उत्पादन के दौरान किसानों को आर्थिक संबल मिलता है।उन्होंने ऐसे किसानों, जिनके अभी तक केसीसी नहीं बने हैं, उन्हें अविलंब केसीसी बनवाने के लिए प्रेरित किया तथा प्रक्रिया को सरल बताते हुए कहा कि किसान अब कृषिका ऐप के माध्यम से भी केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया पारदर्शी एवं त्वरित होगी।डायरेक्टर श्रीमती श्वेता सत्या द्वारा ग्राम बरेठा एवं ग्राम बारूअल में भी किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया गया। ग्राम स्तर पर आयोजित चर्चा में किसानों की समस्याएं सुनी गईं तथा केसीसी से जुड़ी शंकाओं का समाधान किया गया। अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि पात्र किसानों का शीघ्र केसीसी निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

जिला पंचायत सीईओ ने विद्यार्थियों को प्रदान किए प्रमाण पत्र एवं ऑफर लेटर

सीहोर (निप्र)। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एवं आईटीसी मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम के तहत सीहोर में संचालित हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रिकल एवं हेल्थकेयर कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र पर प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं ऑफर लेटर प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया और सेंटर का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में आईटीसी स्टेट टीम के श्री मनीष बक्शी द्वारा आईटीसी द्वारा सीहोर जिले में संचालित बहुउद्देशीय सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी गई।

बरेली सिविल अस्पताल में एनएसव्हीटी तकनीक से की गई पुरूष नसबंदी

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले के सिविल अस्पताल बरेली में एनएसव्हीटी तकनीक से सत्र की पहली पुरूष नसबंदी की गई। बरेली सिविल अस्पताल में शुक्रवार को नसबंदी सर्जन डॉ दीपक गुप्ता एवं उनकी टीम द्वारा समनापुर काछी निवासी 32 वर्षीय पुरूष की एनसएसव्हीटी तकनीक से नसबंदी की गई। इस तकनीक में चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, एक छोटे से छेद से विशेष क्लेम्प का उपयोग कर नसबंदी की जाती है। यह तकनीक अत्यंत सुरक्षित होती है तथा इस तकनीक से की गई नसबंदी में पुरूष अगले दिन से ही अपने सुचारू कार्य कर सकते हैं। शासन द्वारा नसबंदी कराने वाले पुरूष हितग्राही को प्रोत्साहन स्वरूप तीन हजार रू की राशि प्रदान की जाती है।

संस्थाओं का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का किया गया गहन अवलोकन

विदिशा (निप्र)। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत जिले में संचालित संस्थाएं शासकीय संस्था बालिका संप्रेक्षण गृह एवं अशासकीय संस्था शिशु गृह, विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशनकृका धारा 54 के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति के अध्यक्ष व अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, सदस्य सचिव व महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढा कांसवा तथा समिति सदस्य श्रीमती अनीता तिवारी (जेजेबी सदस्य), श्री अतुल शाह एवं श्री राजेश नाडीवाल (सामाजिक कार्यकर्ता) द्वारा संयुक्त रूप से संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है।निरीक्षण के दौरान बालिका संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह में निवासरत बच्चों की वर्तमान स्थिति, मौसम के अनुरूप रहन-सहन की व्यवस्था,

स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य देखरेख एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया। निरीक्षण दल द्वारा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।निरीक्षण उपरांत अधीक्षक बालिका संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह प्रबंधक श्री शुभम गुप्ता सहित संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि संस्थान में नियमित साफ-सफाई, सुरक्षित वातावरण, तथा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं संरक्षण से संबंधित सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बच्चों की देखरेख में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।बालिका संप्रेक्षण गृह में निवासरत बालिकाओं से संवाद के दौरान बालिकाओं द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की जानकारी दी गई, जिसे निरीक्षण समिति द्वारा सराहा गया और भविष्य में कौशल विकास गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के सुझाव दिए गए। उक्तनिरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्थानों में निवासरत बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करना तथा बाल संरक्षण से जुड़े सभी मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना रहा। प्रशासन द्वारा इस प्रकार के निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से किए जाने की बात कही गई।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किया गया 566 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। जिले में 19 दिसंबर को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 396 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 170 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 64 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने इंदौर में अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई जन्म शताब्दी समारोह में सदा अटल महाग्रंथ के आमुख पृष्ठ का विमोचन किया। उन्होंने देवी अहिल्या माता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं गणमान्य नेता उपस्थित थे।

विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे, हम सब मिलकर प्रदेश को बनायेंगे समृद्ध : मुख्यमंत्री

शाजापुर में बनेगा मेडिकल कॉलेज, शुजालपुर को मिलेगा आयुर्वेदिक कॉलेज

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अपनेपन से कुछ और बेहतर करने की नई ऊर्जा मिलती है। शाजापुर जिले ने प्रदेश को विचारों की दिशा दी है। इसलिए विकास में पहला हक भी शाजापुर का है। हम शाजापुर जिले के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। मक्सी के साथ-साथ अब शाजापुर में भी बदलाव की बयार बह रही है। हम सब मिलकर मध्यप्रदेश को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का शाजापुर जिले के जनप्रतिनिधियों, उद्योग संघ, डाक्टर्स एसोशिएशन, कर्मचारी संघ, अधिवक्ता संघ, उद्योग भारती के गणमान्य जनों एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पहारों के साथ अंगवस्त्रम ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर मुख्यमंत्री निवास पर अभिनन्दन कर आभार व्यक्त किया। बीते 2 साल के दौरान शाजापुर जिले को विकास की विभिन्न सौगातें देने के लिए आयोजित इस अभिनंदन समारोह में जिले के जनप्रतिनिधियों ने बीते दो साल की उपलब्धियों का हर्षित होकर जिक्र किया और समवेत् स्वर में 2 साल-बेमिसाल का उद्घोष किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2 मेट्रोपोलिटन एरिया के बीच में शाजापुर सबसे अच्छी जगह है। शाजापुर 2 मेट्रोपोलिटन का केन्द्र बिन्दु है। शाजापुर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। वहीं शुजालपुर में भी आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। मक्सी बहुत पहले औद्योगिक केन्द्र बन गया था लेकिन उसका विकास रूका हुआ था। अब मक्सी भी विकास की नई राह पर है। शाजापुर में भी विकास के कई काम हो रहे हैं। उन्होंने शाजापुर जिले के नागरिकों से कहा कि हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, जो आप चाहेंगे।

शाजापुर के विधायक श्री अरुण भीमावद ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश का गौरव हैं। दो साल की अल्प अवधि में भी मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की काया पलट दी है। शाजापुर जिले को तो सबसे अधिक सौगातें मिली हैं। इसलिए यहां के नागरिक अभिभूत हैं। हम सब हमेशा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के ऋणी रहेंगे। विधायक श्री भीमावद ने कहा कि इन्दौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन रीजन के प्रस्तावित क्षेत्र में शाजापुर जिले के अधिकांश हिस्सा को इस रीजन के दायरे में ले लिया गया है। इससे संपूर्ण जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है, क्योंकि अब इस क्षेत्र के विकास की नई गति मिलेगी।

विधायक श्री भीमावद ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाजापुर विधानसभा के मक्सी क्षेत्र में 8000 करोड़ रुपये निवेश वाली सोलर प्लेट बनाने वाले उद्योग की सौगात दी है। इसका भूमि-पूजन भी हो चुका है। इससे जिले के विकास को नये पंख मिल गये हैं। उन्होंने बताया कि शाजापुर जिला 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं (पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना एवं नर्मदा-कालीसिंध परियोजना) से लाभान्वित हुआ। शाजापुर में मेडिकल कॉलेज की सौगात, आलू-प्याज की मंडी को मंजूरी, शाजापुर शहर का एबी रोज-4 लेन, मक्सी से मोहन बड़ौदिया बायपास निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इन सभी सौगातों से जिले के सभी नागरिक बेहद खुश और अभिभूत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हृदय से आभार व्यक्त किया।

मनरेगा का नाम बदलना गांधी जी का अपमान

भोपाल में वीबी जीरामजी के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन ; बीजेपी पर निशाना साधा

भोपाल (नप्र)। मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ रविवार को भोपाल कांग्रेस कमेटी ने मिंटो हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में भोपाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए।

विरोध जताते हुए भोपाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलना यानि सीधे उनके सम्मान को आघात पहुंचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी यह सहन नहीं करेगी। देश का एक-एक नागरिक भी इसे सहन नहीं करेगा। सरकार को नाम बदलने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज भी लोगों को मनरेगा स्कीम के तहत पैसा नहीं मिल पा रहा है, इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए।

जेपी धनोपिया ने भाजपा पर साधा निशाना

कांग्रेस के सीनियर लीडर जेपी धनोपिया ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) वर्ष 2005 से लगातार पिछले 20 वर्षों से देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबों, आदिवासियों और मजदूर वर्ग को रोजगार देने का काम कर रहा है। यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने खुद 11 वर्षों तक इस योजना का उपयोग किया। इसके बावजूद अचानक इसका नाम बदलने का फैसला लिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में कहा था कि मनरेगा कांग्रेस के शासनकाल का एक स्मारक है। अगर ऐसा है, तो फिर सवाल उठता है कि इस स्मारक को मिटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर भगवान राम का नाम जोड़ना केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास है।

कांग्रेस पार्टी ने रखी ये मांग

भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, लेकिन उनके नाम पर महात्मा गांधी के योगदान को मिटाना न तो उचित है और न ही स्वीकार्य। कांग्रेस पार्टी मानती है कि यह फैसला राजनीतिक संकीर्णता से प्रेरित है। आने वाले समय में जनता इसका हिसाब जरूर मांगेगी। कांग्रेस इस निर्णय का विरोध करती है और मनरेगा के मूल स्वरूप व उसकी पहचान को बनाए रखने की मांग करती है।

प्रदर्शन में कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अवनीश भार्गव, गोविंदपुरा विधानसभा प्रभारी नरेश सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता विनीता साहू, अनोखी मान सिंह, राहुल सिंह राठौर मौजूद रहे।

'नासा से संपर्क' करने वाला शख्स मां को पीटता था

गला रेतकर किया था सुसाइड, केयर टेकर बोला- डॉक्टर और मेड से छेड़छाड़ कर चुका था

भोपाल (नप्र)। भोपाल में आयुष मेहता (45) के खुद का गला रेतकर सुसाइड करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसके केयर टेकर ने कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। केयर टेकर मनीष चौहान ने मीडिया को बताया है कि वह शादी कराने की जिद को लेकर मां से भी मारपीट करता था। वह कई नामचीन महिलाओं के साथ अपने संबंध होने के दावे करता था। यही नहीं दिमाग का इलाज करने वाली महिला डॉक्टर के साथ भी छेड़छाड़ कर चुका था। एक नर्स से तो उसने अश्लील हरकत कर दी थी। हालांकि, मनोरोगी होने के चलते लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे।

2002 से बिगड़ा मानसिक संतुलन

पुलिस के मुताबिक आयुष मेहता नेहरू नगर में रहता था। एमबीए करने के बाद भी घर पर ही रहता था। उसके पिता इंजीनियर थे और प्राइवेट ठेकेदारी करते थे। उनकी मौत हो चुकी है। आयुष का मानसिक संतुलन साल 2002 से बिगड़ा हुआ था। आए दिन बहकी-बहकी बातें करता रहता था।

फारेस्टकर्मी की बाइक चोरी

11 सौ क्वार्टर में एक रात में तीन वारदात, आरोपी बेसुराग

भोपाल (नप्र)। भोपाल के 11 सौ क्वार्टर में रहने वाले वनकर्मी सहित तीन लोगों की अज्ञात बदमाशों ने बाइक चोरी कर ली। वारदात को एक साथ अंजाम दिया गया। आरोपी चेहरों पर नकाब पहने थे। घटना 18 दिसंबर की है, जबकि इसका सीसीटीवी फुटेज रविवार को सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले में हबीबगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। फरियादी राधेश्याम जाटव ने बताया कि वह केरवा बीट में फारेस्ट डिपार्टमेंट के सर्किल इंचार्ज हैं।

18 दिसंबर को घर लौटने के बाद रोज की तरह बाइक को घर के बाहर पार्क किया था। अगले दिन सुबह देखा तो बाइक नहीं दिखी। आस पास पता करने पर दो बाइक और चोरी होने की जानकारी मिली। तब मोहल्ले के लोगों के साथ थाने पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया। पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी चेक करने पर पाया कि आरोपी अलग-अलग आए और बाइक के लॉक को तोड़कर धक्का लगाकर चले गए।

राष्ट्रभक्ति की गूंज के साथ हुई 'राइड फॉर रिस्पेक्ट 2.0'

स्मार्ट सिटी से बोट क्लब तक निकली 14 किमी की देशभक्ति बाइक रैली

भोपाल (नप्र)। देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों और सुरक्षाबलों के सम्मान में रविवार को राजधानी भोपाल में राइड फॉर रेस्पेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया। द ऑटोएडवाइजर और सलोनी ग्रामीण सोसाइटी के संयुक्त देखरेख में निकाली गई यह सामाजिक जागरूकता बाइक रैली ने राष्ट्रभक्ति, एकता और सम्मान का संदेश दिया। रैली का शुभारंभ सुबह 8 बजे स्मार्ट सिटी क्षेत्र से हुआ, जो करीब 14 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बोट क्लब पर संपन्न हुई। बड़ी संख्या में युवाओं, बाइक प्रेमियों और जागरूक नागरिकों ने इसमें भाग लिया। प्रतिभागियों ने हेलमेट पहनकर, अनुशासित ढंग से और यातायात नियमों का पालन करते हुए रैली में हिस्सा लिया।

डोंगला बनेगा गणना, खगोल एवं वैदिक गणित चेतना का केंद्र

भोपाल। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेशभर में गणित के महत्व को रेखांकित करने हेतु विविध जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का मुख्य कार्यक्रम उज्जैन जिले के ऐतिहासिक डोंगला' में संपन्न होगा, जिसे गणना, खगोल और वैज्ञानिक चेतना के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

'डोंगला' प्राचीन काल से ही समय, सूर्य गति, पंचांग निर्माण और गणना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां से काल-गणना, ऋतु परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं का सटीक अध्ययन किया जाता था। इसी गौरवशाली वैज्ञानिक और खगोलिक विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शी संकल्पना एवं सतत प्रयासों के तहत डोंगला को भारतीय ज्ञान परंपरा, खगोल विज्ञान एवं गणितीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विज्ञान, गणित और भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष रुचि इस पहल को नई दिशा दे रही है। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर डोंगला में भारत की वैदिक गणित परंपरा विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यशाला में प्रदेश एवं देश के प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ, शोधार्थी, शिक्षाविद् एवं शिक्षक सहभागिता करेंगे। कार्यशाला के माध्यम से वैदिक गणित की वैज्ञानिकता, आधुनिक गणित से उसका संबंध और शिक्षा में इसके अनुप्रयोग पर गहन विमर्श किया जाएगा। इस अवसर पर सहभागी सूर्य के उत्तरायण होने के खगोलीय क्षण के भी साक्षी बनेंगे, जो भारतीय ज्योतिष, गणित और खगोल विज्ञान की समृद्ध परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का एक दुर्लभ एवं प्रेरक अनुभव प्रदान करेगा परिषद द्वारा इसके साथ ही प्रदेश के लगभग 38 जिलों में 170 से अधिक संस्थाओं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों एवं विद्यालयों में गणित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें व्याख्यान, प्रतियोगिताएं, संवाद सत्र एवं प्रदर्शनी शामिल होंगी। इन कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी रहेगी, जो विद्यार्थियों और आमजन तक गणित की उपयोगिता, तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस-

राष्ट्रीय गणित दिवस महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में गणित के प्रति रुचि बढ़ाना, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा यह संदेश देना है कि गणित देश के वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक विकास की सशक्त आधारशिला है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने रविवार को बैतूल में जनजातीय संस्कृति, शिल्प और वाणिज्य की भावना को समर्पित 'आदि बाजार-2025' का शुभारंभ कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। खण्डेलवाल ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित यह बाजार जनजातीय उद्यमियों को अपने हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय हेतु एक सशक्त मंच प्रदान करता है, जिससे उनकी आजीविका को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के साथ रविवार को बैतूल में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में सहभागिता कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। श्री खण्डेलवाल ने खेलों को युवाओं के सर्वांगीण विकास और अनुशासित जीवनशैली का सशक्त माध्यम बताते हुए प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

आंध्र प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग विजयवाड़ा में संपन्न

भोपाल। आंध्र प्रदेश बॉक्सिंग का गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ के खिलाड़ी देश के लिए गर्व का विषय हैं। डॉ. मिश्र ने कहा कि आंध्र प्रदेश बॉक्सिंग का योगदान राष्ट्रीय खेल परिदृश्य में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। राज्य ने अनेक ऐसे खिलाड़ी और प्रशिक्षक दिए हैं, जिन्होंने अपने अनुशासन, समर्पण और परिश्रम से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विशेष रूप से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित श्री आई. वी. राव, अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री एस. जयराम, विश्व चैंपियन एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त श्रीमती एन. उषा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्री एच. श्रीनिवास तथा एशियाई कांस्य पदक विजेता श्रीमती कविता के योगदान को आंध्र प्रदेश बॉक्सिंग की उपलब्धियों का स्वर्णिम अध्याय बताया।

दक्षिण भारत में बॉक्सिंग की गौरवशाली उपलब्धियाँ रहीं: राकेश ठाकरान (महासचिव)

श्री राकेश ठाकरान (महासचिव) ने इन सभी सम्मानित हस्तियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इनके अनुभव और मार्गदर्शन से आने वाली पीढ़ी के बॉक्सर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊँचाइयों को छुएँगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन आंध्र प्रदेश में बॉक्सिंग के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करता रहेगा।

निशांत वर्मा प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री बंगा राजू सेक्रेटरी जनरल निर्वाचित: सूर्य नारायण राजू (रिटर्निंग आफ़िसर)

आज आंध्र प्रदेश के निर्वाचित पदाधिकारी इस प्रकार रहेः मुख्य संरक्षकः श्री पीवी रामाराव; अध्यक्षङ श्री सागी रामकृष्णा निशांत वर्मा; उपाध्यक्षः श्री जी. ईश्वर राव, श्री के. प्रकाश राव, श्री बी. वी. मोहन कुमार एवं श्री कृष्णा राव; महासचिवः श्री के. बंगारू राजू; कोषाध्यक्षः श्री जी. रामाराव; संयुक्त सचिवः श्री च. रामाराव, श्री माध्य कृष्णा एवं श्री लोवा प्रसाद निर्वाचित हुए। सभी का पुष्प गुच्छ देकर दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश में बॉक्सिंग को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का संकल्पः निशांत वर्मा अध्यक्ष

इस अवसर पर आंध्र प्रदेश में बॉक्सिंग को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का संकल्प निशांत वर्मा अध्यक्ष ने लिया ।स्थानीय मीडिया, वरिष्ठ खेल पत्रकार, समाजसेवी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और राष्ट्रीय पदाधिकारियों से व्यक्तिगत भेंटकर राज्य में बॉक्सिंग के भविष्य को लेकर सकारात्मक संवाद किया।

नरेला बनेगा प्रदेश का आदर्श विधानसभा क्षेत्र, विकास की गति और तेज होगी : विश्वास सारंग

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं नरेला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 70 स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर के समीप सड़क निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को विकास की कई सौगाते दी। भूमिपूजन अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नेपाली समाज द्वारा मंत्री श्री सारंग का पारंपरिक ढोल-नगाड़ों एवं पुष्पवर्षा के साथ आत्मीय, भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत मंत्री श्री सारंग ने समाजजनों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

भाजपा सरकार में नरेला विधानसभा ने विकास की नई पहचान बनाई – मध्याप्रदेश शासन के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा का समग्र, संतुलित और सतत विकास ही मेरा संकल्प है। वर्ष 2008 से पूर्व नरेला क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, किंतु वर्ष 2008 के बाद भाजपा सरकार और हमारे निरंतर प्रयासों से नरेला विधानसभा ने विकास की नई पहचान बनाई है।